खंड

4

सतत विकासः भविष्य पथ

इकाई 11

सतत विकास में नवाचारी नीतियों की भूमिका 171

इकाई 12

निष्पक्षता और न्याय की पारिस्थितिक सीमाओं की पहचान 184

इकाई 13

संसाधन उत्पत्ति और क्षमता वृद्धि के वैकल्पिक तरीके 191

इकाई 14

सतत् विकास में गैर–राज्य हितधारकों की भूमिका 198

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 11 सतत विकास में नवाचारी नीतियों की भूमिका*

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 सतत विकास के लक्ष्य

11.3 सतत विकास नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व

11.4 सतत विकास की दिशा में नवाचारी नीतियां

11.5 निष्कर्ष

11.6 शब्दावली

11.7 संदर्भ लेख

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित बाते समझ सकेंगेः

- सतत विकास की मूल अवधारणा;
- सतत विकास की प्रासंगिकता; और
- सतत विकास में नवाचारी नीतियो का परीक्षण।

11.1 प्रस्तावना

अभी तक हम सतत विकास का अर्थ अच्छे से समझ चुके हैं। अपनी पूर्व इकाइयों में हमने जो कहा है, उसे दोहराते हुए हम यह कह सकते हैं कि सतत विकास की अवधारणा विकास की अवधारणा (पारिस्थितिक बाधाओं के अनुरूप सामाजिक–आर्थिक विकास), आवश्यकताओं की अवधारणा (सभी के जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण) और आगामी पीढ़ियों की अवधारणा (भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन की आवश्यक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों के दीर्घकाल उपयोग की संभावना) पर आधारित है ।

सतत विकास की अवधारणा का सार त्रिपक्षीय संतुलन की अवधारणा से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है सततता के तीन स्तंभों (Pillars) के बीच संतुलन। यह पर्यावरणीय सततता पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने पर केंद्रित है, जो आर्थिक गतिविधियों और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर टिकी है, सामाजिक सततता का संचालन करने के लिए आवश्यक है, जो मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है और समानता, सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण, सांस्कृतिक विविधता, वर्ग और धर्म को सम्मान देती है, और आर्थिक सततता, जो आय और जीवन स्तर के लिए आवश्यक प्राकृतिक, सामाजिक और मानवीय पूंजी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इन सभी स्तंभों के बीच संतुलन के माध्यम से संपूर्ण सतत विकास प्राप्त किया जाता है, हालांकि, आवश्यक स्थिति को प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में सततता के प्रत्येक स्तंभ को अन्य स्तंभो के हितों का सम्मान करना होगा,

* योगदानः डॉ. निवेदिता शर्मा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली

ताकि वे असंतुलन में न आ जाएं। इसलिए, जब सतत विकास का निश्चित स्तंभ सतत बन जाता है, अन्य असतत हो सकते हैं, विशेषकर, जब परिस्थितिक सततता की बात आती है, जिस पर विकास की संपूर्ण क्षमता निर्भर करती है।

दूसरे शब्दों में, सतत विकास का आर्थिक अर्थ है ''विकास जो सतत है''(Development that lasts)। उदाहरण के लिए, एक ऐसा मार्ग, जिसके साथ आज की पीढ़ियों के लिए अधिकतम मानव कल्याण भविष्य के कल्याण में गिरावट का कारण नहीं बनता है (A path along which the maximisation of human well-being for today's generations does not lead to a decline in the future well-being)।

आर्थिक विकास और इसका समर्थन करने वाले प्राकृतिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया सतत विकास के मूल में स्थित हैं। आर्थिक विकास मानव कल्याण के उच्च स्तरों में योगदान देता हैं, और पर्यावरणीय उद्देश्यों की एक श्रृंखला को संबोधित करने के लिए संसाधन प्रदान करता है। हालांकि, आर्थिक विकास से पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक पतन हो सकता है–जब उनके उपयोग के लिए प्रोत्साहन अनुचित हो और बाहरी प्रभावो को आंतरिक न किया गया हो। ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक विकास का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों के समाज के अधिकांश भाग को पूंजी के अन्य रूपों में परिवर्तित करना। आज, आर्थिक और सामाजिक विकास का समर्थन करने वाले कामकाजी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखना विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेष रूप से जब कोई विकल्प उपलब्ध न हो। दुर्लभ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की संभावना, और पर्यावरण पर अधिक दबाव जिसके कारण विश्व की जनसंख्या के लिए इन उपभोग प्रतिमानो (Patterns) का विस्तार से अनुसरण किया जाएगा। यह उपभोग की दुनिया के अधिक सतत प्रतिमानो को प्राप्त करने के महत्व की जांच करता है।

सतत विकास की अवधारणा बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं, गरीबी और असमानता के साथ सामाजिक–आर्थिक मुद्दों और मानवता के लिए स्वस्थ भविष्य के बारे में चिंताओं के बीच वैश्विक संबंधों की बढ़ती जागरूकता का परिणाम है। यह पर्यावरण और सामाजिक–आर्थिक मुद्दों को मजबूती से जोड़ता है। शब्द का पहला महत्वपूर्ण उपयोग 1980 में विश्व संरक्षण रणनीति (World Conservation Strategy) में हुआ था। पर्यावरण और सामाजिक–आर्थिक प्रश्नों को एक साथ लाने की यह प्रक्रिया सबसे प्रसिद्ध रूप से ब्रंटलैंड रिपोर्ट (Brundtland Report) में सतत विकास की परिभाषा ''भविष्य की पीढ़ियों की योग्यता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है'' में व्यक्त की गई थी (WCED, 1987)।

पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग (The World Commission on Environment and Development (WCED), जैसा कि औपचारिक रूप से कहा गया था, विश्व का ध्यान ''मानव पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के तेजी से बिगड़ने और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उसके पतन के परिणामों की ओर आकर्षित करने'' की ओर दिलाया। आयोग की स्थापना में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्पष्ट रूप से दो महत्वपूर्ण विचारों पर ध्यान दियाः पहला, पर्यावरण, अर्थव्यवस्थाओं और लोगों की भलाई का, और दूसरा सतत विकास में वैश्विक स्तर पर सहयोग से अटूट संबंध है।

11.2 सतत विकास के लक्ष्य

हम पहले से ही इस पाठयक्रम की इकाई 4 में सतत विकास के प्रमुख लक्ष्यो की समीक्षा कर चुके हैं। उन्हे दोहराते हुए चलिए उनमे से कुछ लक्ष्यो पर चर्चा करते हैं। सतत विकास के तीन प्रमुख लक्ष्य हैंः

- नए विकास का सृजन करते समय प्राकृतिक संसाधनों के रिक्तीकरण को कम करना;

- पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाए बिना, विकास को सतत व सुरक्षित बनाना; व
- पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं और परियोजनाओं में विकास करने के लिए मौजूदा विकास का पुनःसंयोजन (Retrofitting) करना।

संयुक्त राष्ट्र, गैर–सरकारी संगठन, सहायता संगठन और यहां तक कि सरकार जैसे वैश्विक संगठन निरंतर प्रयासों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सतत विकास एक समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राप्त हो। इन निकायों द्वारा निर्धारित कुछ अन्य सबसे महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्य हैं:

विश्व भर में गरीबी का उन्मूलन (Eradication of Poverty across the World)

ये संगठन मुख्य रूप से कम से कम विकसित और कम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां गरीबी व्यापक है। उनका उद्देश्य स्कूल में भोजन देना, नकद हस्तांतरण, लक्षित खाद्य सहायता, सामाजिक बीमा और श्रम बाजार कार्यक्रम जैसे कौशल प्रशिक्षण, वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरी सब्सिडी, बेरोजगारी बीमा, विकलांगता पेंशन आदि पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार करके एक समान रूप से गरीबी का उन्मूलन करना है।

अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा (Promotion of Good health and Well-being)

यह सतत विकास लक्ष्य जीवन के प्रत्येक चरण में सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना चाहता है। लक्ष्य माता संबंधी और बाल स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, पर्यावरण, संचारी और गैर–संचारी रोगों, सार्वभौमिक स्वास्थ्य विस्तार और गुणवत्ता, सुरक्षित, प्रभावी और सस्ते टीकों और दवाओं तक पहुंच जैसी सभी मुख्य स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को ध्यान में रखता है।

सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान (Provision of Quality Education for all)

यह लक्ष्य समान और समावेशी गुणवत्ता वाली शिक्षा और जीवन में लंबे सीखने योग्य अफसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

स्वच्छ जल और स्वच्छता का प्रावधान (Provision of Clean Water and Sanitation)

यह लक्ष्य विश्व भर में स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, पेयजल और जल संसाधनों की गुणवत्ता और सततता से संबंधित पहलुओं को संबोधित करता है।

समावेशी और सतत औद्योगीकरण का समर्थन करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे का निर्माण (Building up Strong Infrastructure, supporting Inclusive and Sustainable Industrialisation and incubating Innovation)

यह लक्ष्य सतत विकास के तीन पहलुओं को ध्यान में रखता है: औद्योगीकीकरण, बुनियादी ढांचा और नवाचार।

सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच को सक्षम करना (Enabling Access to Affordable and Clean Energy)

यह सतत विकास लक्ष्य सूर्य, पवन, जल–विद्युत, तरल और ठोस जैव–ईंधन, बायोगैस और जियो–थर्मल (Sun, Wind, Hydropower, Liquid and Solid Biofuels, Biogas and Geo-thermal) जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास और विस्तार पर केंद्रित हैं। ऊर्जा के ये नवीकरणीय स्त्रोत वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं और इसलिए पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए आदर्श हैं।

जेंडर समानता प्राप्त करना (Achieving Gender Equality)

पिछले कुछ दशकों में, जेंडर समानता और महिला सशक्तिकरण दीर्घकालीन सतत विकास के लिए अधिकतर सरकारों के लिए एजेंडा रहे हैं। लड़कियों के लिए शिक्षा की पहुंच में सुधार हुआ है, बाल विवाह के प्रतिशत में गिरावट आई है, और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक सफलता व अधिकार प्राप्त हुएं हैं, जैसे मातृ स्वास्थ्य में आकस्मिक बडौतरी।

बोध प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. सतत विकास के अर्थ पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. सतत विकास के प्रमुख लक्ष्यों का विवेचन कीजिए।

.....

.....

.....

.....

11.3 सतत विकास की नीतियों के महत्वपूर्ण तत्व

दीर्घकालिक नियोजन क्षितिज (Long-term Planning Horizons)

विभिन्न प्रकार के संसाधनो पर नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्याप्त ढांचे की अनुपस्थिति में, अल्पकालिक उद्देश्यों पर लक्षित उपायों का चयन किया जा सकता है, भले ही उनके नकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव हो। हालांकि, अलग–अलग लक्ष्यो के बीच अदला–बदली अल्पावधि में प्रबल हो सकता है, दीर्घकालिक समय में मानव निर्मित, प्राकृतिक, मानवीय और सामाजिक पूंजी कल्याणकारी सुधारों का समर्थन करने में एक दूसरे के पूरक होंगी।

मूल्य निर्धारण (Pricing)

सतत परिणामों का समर्थन करने के लिए बाजारों के लिए, कीमतों को उत्पादित की जा रही वस्तुओं और सेवाओं के पूर्ण लागत और लाभों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करने और पर्यावरण को खराब करने वालो के प्रलोभन को समाप्त कर देने, व पर्यावरण को बेहतर बनाने वालो को नई प्रोत्साहन देने की आवश्यकता हो सकती है।

लोक वस्तुओं का वितरण (Delivery of Public Goods)

सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सरकारी हस्तक्षेपों से कई लाभ लोक वस्तुओं (मूल अनुसंधान, सूचना, स्वास्थ्य और शिक्षा) की विशेषताएं हैं। साथ ही, इनमें से कई लोक वस्तुएं वैश्विक है, क्योंकि वे कई देशों को लाभान्वित करेंगी (जैसे वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति के बारे में जानकारी)। इन लोक वस्तुओं के प्रभावी वितरण के लिए भार–सहभाजीत नियमों (Burden-sharing Rules) के द्वारा समन्वय की बाधाओं पर काबू पाने की आवश्यकता होती है, जो व्यक्तिगत देशों की विभिन्न जिम्मेदारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को पहचानते हैं।

लागत प्रभावशीलता (Cost-effectiveness)

नीतियां अपनी आर्थिक लागत को कम करने के उद्देश्य से होनी चाहिए। इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि खर्च किए गए प्रत्येक अतिरिक्त संसाधन की लागत संभावित हस्तक्षेपों की सीमा के बराबर हो। लागत प्रभावशीलता औसत लागतों को कम करने और भविष्य में अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की स्थापना करने की अनुमति देती है।

पर्यावरणीय प्रभावशीलता (Environmental Effectiveness)

नीतियों को चाहिए कि वे निम्नलिखित सुरक्षित करें:

1) **पुनरुत्पादन (Regeneration):** अर्थात नवीकरणीय संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया जाना चाहिए और उनके उपयोग को प्राकृतिक पुनरुत्पादन की दीर्घकालिक दरों से अधिक नहीं होने देना चाहिए;

2) **प्रतिस्थापन (Substitutability):** अर्थात अनवीकरणीय संसाधनों का कुशलता से उपयोग करना चाहिए, और उनका उपयोग उन स्तरों तक सीमित हो, जो नवीकरणीय संसाधनों या पूंजी के अन्य रूपों द्वारा पूरा किया जा सकता हो;

3) **समावेशता (Assimilation):** अर्थात पर्यावरण को खतरनाक या प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थों का उत्पादन इसकी समावेशी क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए, और जमाव (Concentrations) को मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थापित आवश्यक महत्वपूर्ण स्तरों से नीचे रखा जाना चाहिए। जब समावेश की क्षमता प्रभावी रूप से शून्य होती है, तो वातावरण में उनके संचय से बचने के लिए ऐसे पदार्थों की शून्य रिहाई की आवश्यकता होती है; और

4) **अप्रत्यावर्तनीयता से बचना (Avoiding Irreversibility):** अर्थात पारिस्थितिक तंत्रों पर और जैव–भू–रासायनिक और जल–विद्युत या हाइड्रोलॉजिकल चक्रों (Bio-geochemical and Hydrological Cycles) पर मानव गतिविधियों के अपरिवर्तनीय प्रतिकूल प्रभावों से बचना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता को बनाए रखने या सुधारने में सक्षम प्राकृतिक प्रक्रियाओं को मानव गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र का लचीलापन और ले जाने की क्षमता के विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाना चाहिए। ताकि संकट में, संकटग्रस्त और गंभीर प्रजातियों की आबादी का संरक्षण किया जा सके।

नीति एकीकरण (Policy Integration)

विभिन्न क्षेत्रों में असतत नीतियों के कारण असंगत परिस्थितियां हो सकती हैं। विशेष रूप से, क्षेत्रीय नीतियों को प्रायः बाहरी नीतियों के कारण पर्यावरणीय नीतियों द्वारा लक्षित किए बिना प्रस्तुत किया जाता है, जिससे विसंगतियां और नियंत्रण से बाहर प्रभाव (Spill-over Effects) पैदा होते हैं। नीति के अनुकूल सुधार करने के लिए विभिन्न नीतियों में आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लक्ष्यों के बेहतर एकीकरण की आवश्यकता हैं।

पूर्वविधान (Precaution)

पर्यावरण की सुधार क्षमता में महत्वपूर्ण शुरुआत करने से अधिक आशंका का विषय अनिश्चितता हैं। तदनुसार, जब सतत विकास के लिए नीतियां तैयार की जाती है, तो देशों को उन स्थितियों में उपयुक्त रूप से सावधानी या पूर्वविधान रखना चाहिए, जहां वैज्ञानिक निश्चितता का अभाव हो।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (International Cooperation)

अंतर्राष्ट्रीय अंतर–निर्भरता को गहरा करने के साथ, अप्रत्यक्ष प्रभाव अधिक व्यापक हो जाते हैं। जब देश पर्यावरणीय और सामाजिक खतरों का सामना करते हैं, जिसमें वैश्विक आशय होते हैं, तो राष्ट्रीय स्वार्थ पर संकीर्ण ध्यान व्यवहार्य नहीं होता।

पारदर्शिता और जवाबदेही (Transparency and Accountability)

सतत विकास की चुनौती को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भागीदारी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सततता के मानदंड को विशुद्ध रूप से तकनीकी शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से निर्णय हों, वह संभावित परिणामों की संपूर्ण श्रंखला द्वारा सूचित किए जाए, और जनता के प्रति जवाबदेह हों।

11.4 सतत विकास की दिशा में नवाचारी नीतियां

बढ़ती असमानताओं और निरंतर उत्पादन और खपत प्रतिमानों की वर्तमान समस्याएं सत्ता पदानुक्रमों, संस्थानों, संस्कृति और राजनीति के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। राजनीतिक कार्यवाही और सुधार आवश्यक है और निम्नलिखित नौ समूहों में इसे संक्षेप में वर्णित किया जा सकता हैः

i) सभी स्तरों पर लोक वित्त को मजबूत करना (Strengthening Public Finance at all Levels)

वित्त नीतियों में आवश्यक परिवर्तनो के साथ, लोक नीति के स्थान को व्यापक करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए सरकारों को सतत विकास बजट तैयार करना होगा। राजस्व (कर नीति) और वित्त नीति के व्यय (बजट नीति) वित्त नीति के इन दोनों पक्षों को बनाकर ररवा जाना चाहिए। सरकारें पर्यावरणीय संसाधन और सामाजिक नीति के लक्ष्यों के लिए सक्रिय (Proactive) कर नीतियों को आगे बढ़ा सकती हैं और साथ ही साथ अपने मानव अधिकारों के दायित्वों को पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसमें शामिल है– अनवीकरणीय संसाधनों की निकासी और खपत पर कर लगाना, और प्रगतिशील कराधान के उन रूपों को अपनाना, जो गरीब और कम आय वाले लोगों के अधिकारों और कल्याण को प्राथमिकता देते हैं (जैसे धन और संपत्ति के कराधान पर जोर)।

वित्त नीति स्थान को आगे निगम कर प्रोत्साहन (निर्यात प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कर अवकाश सहित), और हानिकारक सब्सिडी से बाहर विशेष रूप से औद्योगिक कृषि और मछली पकड़ने, जीवाश्म ईंधन और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके किया जा सकता है। सैन्य संघर्ष को कम किया जाना चाहिए, और नागरिक संघर्ष की रोकथाम और शांति निर्माण के लिए संसाधन बचत को दूसरों के बीच पुनः आवंटित किया जाना चाहिए। यदि प्राथमिकताओं को उचित रूप से परिभाषित किया गया है, तो वित्त नीतियां सामाजिक–आर्थिक असमानताओं को कम करने, भेदभाव को समाप्त करने और स्थायी उत्पादन और खपत पैटर्न में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली साधन बन सकती है। आवश्यक सुधार केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं होने चाहिए। नगरपालिका वित्त प्रणालियों के विकास और स्थानीय अधिकारियों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता सहित सभी स्तरों पर सार्वजनिक या लोक वित्त को मजबूत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय वित्त प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण के लिए मौलिक शर्त यह है कि वैश्विक कर सहयोग को मजबूत किया जाए, ताकि हानिकारक कर की दौड़ और कर दुरुपयोग की विभिन्न योजनाओं का सामना किया जा सके।

ii) उत्पादकता क्षमताओं के विस्तार के लिए लोक व्यय (Public Expenditure for the expansion of Productive Capacities)

व्यय पक्ष पर, लोक वित्त के आवंटन के लिए प्राथमिकताओं और श्रेष्ठ अनुक्रमण की पहचान करने और विभिन्न लक्ष्यों के बीच संयुक्त संतुलन खोजने की

चुनौतियां हैं। सतत विकास के सामाजिक स्तंभ–जैसा कि कई एस डी जी या सतत विकास लक्ष्य में परिलक्षित होता हैं–स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए लोक सेवाओं में सुधार करने के लिए लोक व्यय में पर्याप्त वृद्धि की मांग की जाती हैं। आर्थिक विकास को गति देने के दृष्टिकोण से, आधारिक संरचना पर व्यय में वृद्धि करना और उत्पादक गतिविधियों के लिए लोक समर्थन सेवाएं अपरिहार्य हैं।

इन श्रेणियों के भीतर भी सभी जरूरतों और उद्देश्यों के लिए एक ही समय में व्यय को नहीं बढ़ाया जा सकता। वर्तमान व्यय में, अत्यधिक गरीबी के लक्षणों को कम करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूंजीगत व्यय को जो संरचनात्मक परिवर्तन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन क्षेत्रों में आधारिक संरचना के निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां उत्पादक क्षमताओं के विस्तार पर बाधाएं अधिक दृढ़ता से महसूस की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त सार्वजनिक या लोक वसूली घरेलू उद्योगों और सेवाओं के विस्तार और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्थानीय स्तर पर आदानो के उत्पादन के लिए लोक वसूली को महत्व देना क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान बन सकता है, जो संरचनात्मक परिवर्तन के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। अंत में, सब्सिडी के विभिन्न रूप उत्पादकों की लागत संरचना को प्रभावित करके या आवश्यक आदानों तक पहुंच को सक्षम करके संरचनात्मक परिवर्तन को तेज करने में और उत्पादक क्षमताओं के निर्माण में सहायक हो सकते हैं।

iii) नए कानूनी साधनों का बेहतर उपयोग या निर्माण (Better use or creation of New Legal Instruments)

जलवायु परिवर्तन समझौतों और उनके कार्यों के संदर्भ में सरकारों द्वारा किए गए वादों के बीच अधिक अंतर (Gap) ने जवाबदेही (Accountability) के लिए एक नया दृष्टिकोण तैयार किया है। पिछले कुछ वर्षों में अदालती मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो सरकारों की जलवायु परिवर्तन नीति को चुनौती देना चाहते हैं। 2015 से, जलवायु परिवर्तन के मामले, जो सरकारी जलवायु परिवर्तन नीतियों की अपर्याप्तता को चुनौती देते हैं, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, नार्वे, भारत, कोलंबिया और संयुकत राज्य अमेरिका सहित देशों में दायर किए गए हैं।

निगमों की जिम्मेदारी को लागू करने के लिए, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन उद्योग में भी साधन के रूप में मुकदमेबाजी का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की बढ़ती दृश्यता से यह आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में सफल मामलों की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे मुकदमेबाजी जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से प्रभावी उपकरण बन जाएगी।

मानवाधिकार तंत्र सरकारों को जवाबदेह रखने के लिए उपकरणों का एक और संग्रह (Set) प्रदान करता है। खाद्य और पोषण अधिकार के संबंध में, खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organisation -FAO) व विश्व खाद्य सुरक्षा समिति (Committee on World Food Security-CWFS) द्वारा समर्थित कई स्वैच्छिक दिशानिर्देशों का बहुत महत्व है, विशेष रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में पर्याप्त भोजन के अधिकार पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश, खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में पट्टेदारी, मत्स्य पालन और वन (कार्यकाल दिशानिर्देश) के उत्तरदायी शासन पर स्वैच्छिक दिशानिर्देश और सतत लघु–स्तरीय मत्सय पालन (Sustainable Small-scale Fisheries) को सुरक्षित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश। राष्ट्रीय नीतियों और स्थायी कार्यनीतियों में उनके कार्यान्वयन और

अनुवाद को ओर अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों की प्रासंगिकता और अनुप्रयोग क्षेत्रीय सीमाओं पर समाप्त नहीं होते। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का तात्पर्य है, देश के क्षेत्र से बाहर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों सहित सभी मानवाधिकारों की पूर्ति का सम्मान, रक्षा और समर्थन करना।

कंपनियों के मानव अधिकारों के उत्तरदायित्व के संबंध में अभी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन (Legally-binding Instrument) की आवश्यकता है। मानवाधिकार परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत, अंतरराष्ट्रीय निगमों और अन्य व्यावसायिक उद्यमों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए इस तरह के साधन (या संधि) को विस्तृत करने के लिए अंतर–सरकारी कार्य समूह की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सरकारों को इस 'संधि प्रक्रिया' को गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें सक्रिय रूप से संलग्न होना चाहिए। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र को संयुक्त राष्ट्र– व्यापार बातचीत के लिए या पारस्परिक विचार–विमर्श के लिए नियामक ढांचा विकसित करना चाहिए। इसे वैश्विक भागीदारी में संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी के लिए और निजी क्षेत्र में सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र पहल के आकार और संरचना के लिए न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना चाहिए। इन मानकों से संयुक्त राष्ट्र की नीतियों पर अनुचित निगम प्रभाव को रोका जा सकता है और उन कंपनियों को रोका जा सकता है, जो संयुक्त राष्ट्र की घटनाओं में भागीदारी से और संयुक्त राष्ट्र के वसूली अनुबंधों के लिए योग्यता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत पर्यावरणीय, सामाजिक और मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करती है, या अन्यथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है (भ्रष्टाचार के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को तोड़ने से, संयुक्त राष्ट्र के वैशिक समझौतों के विरुद्ध पैरवी करने से, करों को बचाने आदि के माध्यम से)।

iv) सतत विकास के उपायों और संकेतकों मे सुधार (Refining Measures and Indicators of Sustainable Development)

2030 एजेंडा को अपनाने के लगभग 3 तीन वर्ष पश्चात एस डी जी या सतत विकास लक्ष्यों के कार्यन्वयन में प्रगति (या प्रतिगमन-Regression) का आंकलन करने के लिए संकेतक अभी भी तर्क–वितर्क कर रहे हैं। एस डी जी की सार्वभौमिकता, उनकी व्यापक प्रकृति और परस्पर संबंध अधिकांश राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों को चुनौती दे रहे हैं। गरीबी, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, जेंडर, असमानता और शासन जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अभी भी अत्यधिक डेटा अंतराल हैं। आज तक, 169 एस डी जी लक्ष्यों में से केवल 50 प्रगति मूल्यांकन के लिए तैयार हैं। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग (UN Statistical Commission) के सदस्यों द्वारा समर्थित 232 संकेतकों में से नियमित माप मानदंड की कमी (68) और पर्याप्त डेटा कवरेज की कमी (66) हैं। इससे भी और खराब, जेंडर–विशिष्ट संकेतकों की निगरानी के लिए आवश्यक डेटा का एक तिहाई से भी कम वर्तमान में उपलब्ध है। जैसा की निगरानी और समीक्षा प्रक्रिया जारी है, सरकारों को आवश्यक संसाधन प्रदान करने और इन डेटा (आंकड़ों) अंतरालों को बंद करने की क्षमताएं विकसित करनी चाहिए।

हालांकि, पर्याप्त एस डी जी संकेतको की खोज केवल संसाधनों का प्रश्न नहीं है। सहमत कार्यप्रणाली और उपलब्ध आंकड़ों के साथ संकेतको का संग्रह एस डी जी की घोषित परिवर्तनकारी प्रकृति के अधिकांश पहलुओं को छोड़ देता है। एस डी जी के प्रतिमान परिवर्तन (Paradigm Shift) के रूप में सही ढंग से प्रशंसा की जाती है कि कैसे वह असमानताओं के बारे में चिंता व्यक्त करता है, और सार्वभौमिक रूप से उचित गरीबी की परिभाषा के विस्तार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय

समुदाय के सतत विकास को सूचित करता है। लेकिन यह वह तस्वीर नहीं है, जो स्तर 1 संकेतकों के वर्तमान संग्रह से निकलती है। विशेष रूप से, देशों के भीतर और बीच असमानताओं पर संकेतक बिल्कुल अपर्याप्त है। शायद यह दूसरे तरीके से शुरू करने का समय है, 2030 एजेंडा की परिवर्तनकारी दृष्टि और 17 एस डी जी के मूलभूत प्रयोजन पर विचार करना और उन वचनों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिनिधि संकेतक या सूचकांक खोजना, 169 लक्ष्यों में से प्रत्येक के लिए व्याख्या और डेटा एकत्र करना, जो संपूर्ण और दर्दनाक धीमी गति से समानांतर प्रक्रिया में है। इस तरह की प्रक्रिया एस डी जी के लक्ष्य के कार्यान्वयन में योगदान भी दे सकती है ''सतत विकास पर प्रगति के माप को विकसित करना, जो सकल घरेलू उत्पाद का संपूरक है'' और मानव अधिकारों के माप और कल्याण के वैकल्पिक उपायों के बारे में व्यापक विचार–विमर्श को ध्यान में रखता है।

v) वैश्विक शासन अंतराल को बंद करना और सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना (Closing Global Governance Gaps and Strengthening the Institutional Framework for Sustainable Development)

2030 एजेंडा कार्यान्वयन प्रक्रिया में आवश्यक नीती सुधारों की प्रभावशीलता राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत, अच्छी तरह से सुसज्जित लोक संस्थानों के अस्तित्व पर निर्भर करती है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, सरकारों और संसदों की संस्थागत व्यवस्थाओं में 2030 का एजेंडा और एस डी जी की व्यापक विशेषता को प्रतिबिंबित करना आवश्यक है। अधिक प्रभावी और स्पष्ट वैश्विक शासन का निर्माण करना एक निरर्थक अभ्यास होगा, यदि यह प्रभावी राष्ट्रीय समकक्षों में 'प्रतिबिंबित' और 'स्वामित्व' द्वारा नहीं है। वैश्विक स्तर पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को 'उद्देश्य के लिए उपयुक्त' ('Fit for Purpose') बनाने के दावे के लिए मौजूदा संस्थानों के सुधार और उन क्षेत्रों में नए निकायों के निर्माण की आवश्यकता है, जहां शासन अंतराल विद्यमान है।

इन शासन की कमियो (Gaps) को खत्म करने के लिए न केवल संसाधनों के असमान वितरण पर काबू पाने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, बल्कि भागीदारी और निर्णय लेने की पहुंच, भी आवश्यक होती है। दो प्रमुख सिफारिशें हैं, जिनका अत्यधिक महत्व है और संस्थागत सुधारों के ठोस उदाहरण देते हैं, जिनकी आवश्यकता भी है। प्रथम, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में, अंतर–सरकारी निकाय की स्थापना करना जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संयुक्त राष्ट्र राज्य के सदस्य वैश्विक कर नियमों के सुधार में समान रूप से भाग ले सकते हैं; और द्वित्तीय, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर ऋण पूर्वाकलन संस्थान (Debt Workout Institution) का निर्माण करना, जो ऋण पुनर्गठन प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए लेनदारों और देनदारों से स्वतंत्र हों।

वैश्विक स्तर पर, 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए अनुमानित और विश्वसनीय धन के प्रावधान की भी आवश्यकता है। विशेष रूप से, सरकारों को स्वैच्छिक, गैर–अभ्यन्तर और निर्धारित योगदान और परोपकारी धन पर बढ़ती निर्भरता के प्रति रुझान को प्रतिवर्तित कर देना चाहिए। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। सतत विकास के लिए सिद्धांतों, लक्ष्यों और नीतियों को मजबूत करने और वैश्विक शासन वास्तुकला में असमानता को दूर करने के लिए, मानक स्थापना, नीति समन्वय और निरीक्षण के लिए एक प्रभावी अंतर–सरकारी निकाय आवश्यक है।

सरकारों ने 2030 के एजेंडे में निर्णय लिया गया कि सामान्य महासभा और आर्थिक और सामाजिक परिषद (General Assembly and the Economic and Social Council) की संयुक्त तत्वावधान में उच्च–स्तरीय राजनीतिक मंच (High-Level

Political Forum -HLPF-एच एल पी एफ) की अनुवर्ती और समीक्षा की देखरेख, और राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने में केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एजेंडा प्रासंगिक और महत्वाकांक्षी बना हुआ है। हालांकि, अन्य नीतिगत रंगभूमि की तुलना में, जैसे सुरक्षा परिषद या मानवाधिकार परिषद (Security Council or the Human Rights Council) की नीतियां व एच एल पी एफ कमजोर बनी हुई हैं और वर्ष में केवल आठ दिनों की एक बैठक के कारण पूरी तरह से प्रभावी रूप से अपने जनादेश को पूरा करने में असमर्थ है। एच एल पी एफ 2019 राज्य और सरकार के प्रमुखों के स्तर पर, एच एल पी एफ की आगामी समीक्षा, और संयुक्त राष्ट्र 2020 की 75 वीं वर्षगांठ संयुक्त राष्ट्र में सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करने और नवीकरण के नए अवसर प्रदान करती है।

उपर वर्णित राजनीतिक और संस्थागत सुधारों को लागू करने के लिए (और इस रिपोर्ट में निम्नलिखित अध्यायों और एस डी जी की सुर्खियों में) सभी सरकारों की वैश्विक सहमति (जिसे वर्तमान भू–राजनीतिक वातावरण में पहुंचना लगभग असंभव है) की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय या यहां तक कि उप– राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को आकार देने या संयुक्त राष्ट्र के संस्थागत ढांचे के भीतर समान विचारधारा वाले देशों की पहल, शुरू करने के लिए पर्याप्त स्थान है। इसके अतिरिक्त, मौलिक नीति परिवर्तन प्रमुख प्रवचनों और मानसिकता के परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें उपर से आदेश नहीं दिया जा सकता है। 2030 एजेंडा के शीर्षक में जैसे घोषित किया गया कि हमारे विश्व का परिवर्तन सभी स्तरों पर स्थानीय कार्यवाही से लेकर वैश्विक शासन सुधार तक और सभी सामाजिक अभिनेताओं द्वारा एक साथ होना चाहिए। यह प्रमुख चुनौती है, लेकिन 2030 की प्रक्रिया द्वारा बड़ा अवसर भी प्रदान किया गया है।

vi) बेहतर आधारिक संरचना बनाना (Creating better Infrastructure)

भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, संपूर्ण देशों में विशिष्ट बुनियादी ढांचे/आधारिक संरचना में विशेष रूप से अंतर करने की आवश्यकता है, फिर भी, सभी कम विकसित देश (Least Developed Countries-LDCs) में, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक आधारिक संरचना में पर्याप्त रूप से निवेश की आवश्यकता होती है, जिसका जनसंख्या के कल्याण जैसे स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता उपयोगिताओं, सार्वजनिक या लोक परिवहन और शिक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आंशिक रूप से इनके साथ अतिव्यापी आर्थिक अवसंरचना में ''परिवर्तनकारी'' निवेश (Transformational Investments) हैं, जो एस डी जी प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य है, क्योंकि वे उत्पादक क्षमताओं में निजी निवेश को सक्षम और प्रेरित करते हैं। इस तरह के परिवर्तनकारी आधारिक संरचना के निवेश में शामिल है, उदाहरण के लिए बिजली, दूरसंचार और परिवहन और रसद सुविधाएं। परिवर्तनकारी अवसंरचना में निवेश संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए निजी निवेश का एक एक अनिवार्य पूरक है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारिक संरचना निवेश प्रायः मानव विकास और शहरी क्षेत्रों की तुलना में विविधीकरण की सुविधा के लिए और भी महत्वपूर्ण है।

vii) वैज्ञानिक और तकनीकी विकास और नवाचार (Scientific and Technological Development and Innovation)

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (Science, Technology and Innovation -STI– एस टी आई) नीतियां औद्योगिक नीति से निपटने से संबंधित है, लेकिन वे कृषि में पर्यावरणीय रूप से मजबूत उत्पादकता वृद्धि, आधुनिक सेवाओं के विकास और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और अल्पीकरण की चुनौती को पूरा करने के लिए भी प्रासंगिक है। सामाजिक और मानव विकास के लक्ष्यों के प्रतित्वरक

(Accelerated) प्रगति में एस टी आई नीतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को प्रत्येक कम से कम विकसित देश की आर्थिक संरचना और इसकी सरकार और व्यावसायिक क्षेत्रों की क्षमताओं में तकनीकी विकास के स्तर पर उचित रूप से जांच करने की आवश्यकता हैं। इस प्रकार, तकनीकी प्रगति का मुख्य रूप से उन प्रौद्योगिकियों का अनुकूलन है, जो देश के लिए नए हैं–हालांकि दुनिया के लिए और उत्पादन प्रक्रियाओं के तकनीकी उन्नति के लिए आवश्यक नहीं हैं।

इस अर्थ में तकनीकी प्रगति घरेलू अनुसंधान और विकास और अधिगम के प्रयासों, या अधिक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से हो सकती है। उन्नत विदेशी प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से घरेलू या विदेशी निवेशकों द्वारा मशीनरी और उपकरणों के आयात के माध्यम से प्राप्त की जाती है, लेकिन यह विदेशी लाइसेंसिग का रूप भी ले सकती है। चूंकि प्रौद्योगिकी मशीनरी और उपकरणों में बड़े पैमाने पर समाविष्ट है, प्रौद्योगिकी का अनुकूलन भी निवेश के स्तर में निकटता से संबंधित है और नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित है। इसलिए, यह आवश्यक है कि एस टी आई को प्रत्यक्ष नीति समर्थन विकास नीति के अन्य क्षेत्रों के साथ निकट समन्वय में डिज़ाइन किया जाए।

viii) प्रौद्योगिकीय क्षमताओं के अनुरूप मानव कौशल का उन्नयन (Upgrading Human Skills in line with Technological Capabilities)

उत्पादक परिवर्तन में कौशल उन्नयन, तकनीकी प्रगति और निवेश संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया में परस्पर–निर्भरता है। एक ओर, कार्यबल (कर्मचारियों की संख्या) के बीच तकनीकी कौशल और ज्ञान की कमी से मौजूदा पूंजी स्टॉक के उपयोग के अंतर्गत संचालन किया जा सकता है। यह विस्तार करने के लिए प्रेरण ा में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जैसाकि प्रायः क्रम विकसित देश या एल डी सी में होता है। दूसरी ओर, बेहतर शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्नयन करने वाले कौशल उत्पादकता में वृद्धि और संरचनात्मक परिवर्तन में योगदान करेंगे, यदि बेहतर प्रशिक्षित कर्मचारी रोजगार पाते हैं। इसके लिए पूंजी उपकरणों के उन्नयन और विस्तार की आवश्यकता है। इसलिए, इन क्षेत्रों में लोक नीतियों को उद्यमों की आवश्यकताओं के साथ अच्छी तरह से समन्वित किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि ज्ञान के विशिष्ट निर्माता, जैसे अनुसंधान संस्थान, उस ज्ञान के संभावित उत्पादक उपभोगकर्ताओं की मांगों का जवाब दे।

ix) तेजी से बढ़ते श्रम बल के लिए रोजगार का निर्माण करना (Employment Creation for a Rapidly Growing Labour Force)

उत्पादकता वृद्धि के साथ सभी के लिए तेजी से रोजगार का निर्माण करना शायद कम विकसित देशों में आर्थिक नीतियों के लिए सबसे गंभीर चुनौती है, जो तेजी से बढ़ते श्रम बलो और पहले से ही बढ़ते स्तर की बेरोजगारी की विशेषता है। रोजगार नीतियों को दो पूरक उद्देश्यों का पालन करना चाहिएः

- तेजी से बढ़ती श्रम शक्ति को देखते हुए नौकरियों की संख्या का विस्तार करना; और
- गरीबी को कम करने और घरेलू मांग को मजबूत करने के लिए उत्पादकता वृद्धि के अनुरूप इन नौकरियों द्वारा उत्पन्न आय को बढ़ाना।

अतीत में, विकासशील देशों में बाजार उदारीकरण के कारण प्रायः औद्योगिक क्षेत्र में उच्च श्रम उत्पादकता का संचालन हुआ, लेकिन इस क्षेत्र का कुल रोजगार गिरा। कई मामलों में, श्रमिक औद्योगिक क्षेत्र से उत्पादकता क्षेत्रों में चले गए, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में। प्रतिलोम (Reverse) संरचनात्मक परिवर्तन की यह घटना बताती है कि संरचनात्मक परिवर्तन के संदर्भ में रोजगार सृजन के लिए सावधानीपूर्वक विस्तृत लोक नीतियों की आवश्यकता होती है।

विकास आवश्यक स्थिति है, लेकिन रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए नीति निर्माताओं के लिए चुनौती एक तरह के निवेश को बढ़ावा देना है, जो रोजगार वृद्धि के साथ उत्पादकता वृद्धि को जोड़ती है। एक मजबूत और सतत निवेश–विकास–रोजगार संबंध में प्रवेश बिंदु निवेश होता है, जो एक नेक चक्र को गति में लाता है, जो ऐसा रोजगार पैदा करता है, जो आय में वृद्धि करने की जरूरतों पर जोर देता है, जो आगे जाकर उपभोग को जन्म देता है, जो औसत मांग के विस्तार का समर्थन करता है।

बोध प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए।

1. सतत विकास की ओर महत्वपूर्ण नवाचार नीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

11.5 निष्कर्ष

संक्षेप में, सतत विकास आज हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का एक साधन है, जो समय के साथ बनाए रखा जा सकता है। यह हमें उन सभी को महत्व देना सिखाता है, जो हमारी भलाई में योगदान देते हैं, भले ही परिस्थितिकी प्रणालियों की तरह उनके ''मूल्यों'' की आसानी से गणना नहीं की जा सकती हैं। नागरिकों, वैज्ञानिकों या नीति निर्माताओं के रूप में हमारा काम यह है कि हमारे अस्तित्व के लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसको शामिल करें। सतत विकास ने इस तर्क–वितर्क को बहुत प्रभावित किया है कि कैसे हम, समाज और सरकारें बेहतर, और अधिक संतुलित जीवन जीने की तलाश में अपनी भूमिका की कल्पना करती हैं। इस इकाई ने सतत विकास की मूल अवधारणाओं, घटकों और इसे प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा की है।

11.6 शब्दावली

मानव अधिकार परिषद (Human Rights Council): मानव अधिकार परिषद का उद्देश्य है विश्व में मानव अधिकारों को बढाना व संरक्षण करना । यह सयुंक्त राष्ट्र मानव अधिकार कमीशन कें स्थान पर 15 मार्च मे स्थापित हुआ।

विश्व संरक्षण रणनीति (World Conservation Strategy): विश्व परिरक्षण कार्य–नीति का मुख्य उद्देश्य आवश्यक पारिस्थितिक प्रर्कियाओं व जीवन रक्षक प्रणाली को बनाए रखना, आनुवंशिक विविधता का संरक्षण करना, व उपजातियों और परितंत्र के सतत उपयोग सुनिश्चित करना है।

11.7 संदर्भ लेख

Ensah, J. (2019). Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action: Literature Review. *Cogent Social Sciences*. 5(1), 1653531.

Hopwood, B., Mellor, M., & O'Brien, G. (2005). Sustainable Development: Mapping Different Approaches. *Sustainable Development*. 13(1), 38-52.

Kumar *et al*. (2016). *Strategies for Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in South Asia: Lessons from Policy Simulations*. UNESCAP. Retrieved

from https://www.unescap.org/sites/default/files/20160825_SDG%20PolicyStrategies%20South%20Asia_SSWA_DP_1601_final_for%20upload.pdf.

OECD (2016). *Better Policies for Sustainable Development 2016. A New Framework for Policy Coherence*. Paris: OECD Publishing.

Redclift, M. (1992). The Meaning of Sustainable Development. *Geoforum*. *23*(3), 395-403.

Starneg, T. & Bayley, A. (2008). Sustainable Development: Linking Economy, Society and Environment. OECD publications.

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**
   - यह आवश्यकताओं की अवधारणा पर आधारित हैं।
   - यह भविष्य की अवधारणा पर आधारित है।
   - तीन स्तभों–पर्यावरणीय सततता, सामाजिक सततता और आर्थिक सततता के बीच संतुलन की आवश्यकता है।
   - यह एक विकास है, जो टिकाउ या सतत है।
   - इसमें आज की पीढ़ी के लिए मानव कल्याण का अधिकतम समावेश है, जो भविष्य की भलाई में कमी नहीं करता।
2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**
   - नए विकास का सृजन करते समय प्राकृतिक संसाधनों की कमी को कम करना।
   - पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचाए बिना विकास को बनाए रखा जा सकता है और सतत रखा जा सकता है।
   - पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं और परियोजनाओं में उन्हें बनाने के लिए मौजूदा विकास को वापस लेने के तरीके प्रदान करना।

बोध प्रश्न 2

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**
   - सभी स्तरों पर लोक वित्त को मजबूत करना।
   - उत्पादक क्षमताओं के विस्तार के लिए लोक व्यय।
   - नए कानूनी उपकरणों का बेहतर उपयोग या निर्माण।
   - सतत विकास के उपायों और संकेतको का संशोधन।
   - वैश्विक शासन अंतराल को कम करना और सतत विकास के लिए संस्थागत ढांचे को मजबूत करना।
   - बेहतर आधारिक संरचना का सृजन करना।
   - वैज्ञानिक और तकनीकी विकास और नवाचार।
   - प्रौद्योगिकी क्षमताओं के अनुरूप मानव कौशल का उन्नयन।
   - तेजी से बढ़ते श्रम बल के लिए रोजगार सृजन।

इकाई 12 निष्पक्षता और न्याय की पारिस्थितिक सीमाओं की पहचान*

इकाई की रूपरेखा

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 पर्यावरणीय न्याय और आदिवासियों के अधिकारों के बीच सबंध

12.3 पर्यावरणीय संरक्षण के लिए मूल निवासियों का महत्व

12.4 निष्कर्ष

12.5 शब्दावली

12.6 संदर्भ लेख

12.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित बाते समझ सकेंगे :

- पारिस्थितिक न्याय की अवधारणा;
- पर्यावरणीय न्याय और आदिवासियों के अधिकारों के बीच संबंध; और
- पर्यावरणीय संरक्षण के लिए मूल निवासियों का महत्व।

12.1 प्रस्तावना

हाल ही के दिनों में, पर्यावरणीय गुणवत्ता और मानवीय समानता के बीच संबंधों पर चिंता बढ़ रही है। विश्व के किसी भी भाग में पर्यावरणीय निम्नीकरण का संबंध सामाजिक न्याय, निष्पक्षता, अधिकारों और लोगों के जीवन की गुणवत्ता जैसे प्रश्नों के साथ व्यापक दृष्टि से जुड़ा है। वैश्विक स्तर पर मानव जाति बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रही है, जो पर्यावरण के साथ अपने संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता का संकेत देती है।

वैश्विक नेताओं, वैज्ञानिकों कार्यकर्ताओं और शिक्षावादियों ने जलवायु और पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के परिवर्तन के बारे में निरंतर चेतावनी दी है, जिसे शीघ्र और सामूहिक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है। यह परिवर्तन–काल आर्थिक प्रणालियों, भूमि की लागत और वितरण, ऊर्जा उपलब्धता और समुदाय और शासन क्षमताओं को प्रभावित करेगा।

जैसे–जैसे मानव समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र गिरावट और कमी का सामना कर रहे हैं, पारिस्थितिक न्याय (Ecological Justice) की खोज हमें यह विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि लोग इससे कैसे प्रभावित होते हैं और इनके समर्थन में काम करते हैं, व मानवता और पर्यावरण के बीच टूटे हुए संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने की मांग करते हैं। इस तरह के सामंजस्य में शासन, व्यापार और सामुदायिक कार्य सम्मिलित करते हुए, एक बहू–हितधारक दृष्टिकोण (Multi-stakeholder Approach) शामिल होता है। इसमें नैतिक परिवर्तन भी शामिल हैं, जहां मजबूत संबंध न्याय की खोज में केंद्रीय सिद्धांत बन जाते हैं।

---

* योगदानः डॉ. निवेदिता शर्मा, सहायक प्रोफेसर,सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली

पारिस्थितिक न्याय सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय दोनों हैं। पारिस्थितिक न्याय इस सिद्धांत पर आधारित है कि ''सबकुछ परस्पर संबंधित है'' ('Everything is Interrelated'), और पर्यावरणीय क्षेत्र में नैतिक कार्यवाही (Ethical Action) सामाजिक स्तर पर निष्पक्षता के लिए केंद्रीय हैं। न्याय को जब पारिस्थितिक अर्थ में देखा जाता है, तो इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय दोनों शामिल होते हैं। यही है, पारिस्थितिक न्याय, जो ऐतिहासिक समझ और ताकतों के उभरते हुए दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, और जो हमारे विश्व को आकार देता हैं। सामाजिक न्याय निष्पक्षता और समानता पर निर्भर करता है, सभी लोगों के मूल्य को पहचानता है, और इस आवश्यकता पर बल देता है कि सभी लोगों को जाति, जेन्डर, राष्ट्रीयता, धर्म या अन्य विभेदक कारकों की परवाह किए बिना, जीवन को परिपूर्ण करने का अवसर प्रदान किया जाए।

पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है, जिसमें सम्मिलित हैं:

i) पर्यावरणीय वस्तुओं और सेवाओं का उचित वितरण;

ii) निर्णय–निर्माण और वितरण में मानव और गैर–मानव हितों की पहचान;

iii) विचारात्मक और लोकतांत्रिक भागीदारी का अस्तित्व; तथा

iv) व्यक्तियों, समूहों और प्रकृति के गैर–मानवीय भागों के बीच क्षमताओं का निर्माण।

पर्यावरणीय अन्याय विभिन्न तंत्रों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, जैसा कि सरकारी नियोजन और विनियमन, निजी और निगम हित, जो विशिष्ट क्षेत्रों और स्थानों का शोषण करते हैं। इस शोषण में आदिवासियों की भूमिका और उनकी चिंताओं को प्रायः मुख्यधारा विषयक पर्यावरणीय न्याय के विचार–विमर्श और साहित्य से अलग किया गया है। यह अदृश्यता अधिकतर सामान्य गलत सूचना का परिणाम है, और साथ ही इस देश में जनजातियों और उनकी विशिष्टता, अधिकारों और विशेष कानूनी और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी की कमी है।

12.2 पर्यावरणीय न्याय और आदिवासियों के अधिकारों के बीच सबंध

2011 की जनगणना के अनुसार, आदिवासी लोगों की संख्या 104.2 मिलियन (Million) है, जो देश की 1.2 बिलीयन आबादी का 8.6 प्रतिशत है। यह विश्व के किसी भी देश में सबसे बड़ी स्थानीय या मूल आबादी है, जिसमें भारत के भौगोलिक भू–भाग का 22 प्रतिशत भाग है। वे जिन क्षेत्रों में रहते हैं, वे देश के सबसे अविकसित क्षेत्र हैं। उनमें से लगभग 93 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है (पल्टासिंह और पालीवाल-Paltasingh & Paliwal, 2014)।

इसके अतिरिक्त, जंगलों में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, वे इन जंगलों से उत्पन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं, बदले में, उन्हें जंगल को संरक्षित करने में रुचि है, क्योंकि यह उनकी जीवन समर्थन (Life Support) प्रणाली हैं। लेकिन वैश्वीकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण मूल निवासी उन पारंपरिक भूमि और क्षेत्रों तक अपनी पहुंच खो रहे हैं, जिन पर उनकी आजीविका निर्भर है। इसने शहरी और औद्योगिक मांगों को पूरा करने के लिए वनों की कटाई की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे जनजातियों की आजीविका का स्वरूप बहुत प्रभावित हुआ है। यह प्रवृत्ति बड़ी संख्या में जनजातियों को उनके आवासों से विस्थापित करने के लिए जिम्मेदार है।

दुर्भाग्यवश, वन्यजीव प्रथम, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट और टाइगर रिसर्च एंड कंजर्वेशन ट्रस्ट (Wildlife First, Wildlife Trust of India, and Tiger Research and Conservation Trust) सहित कई भारतीय वन्यजीव और संरक्षण संगठनों के आदिवासियों पर जंगलों की जैव–विविधता को नष्ट करने का आरोप लगाया है, और अदालत में उन्हे भूमि को खाली करने के लिए याचिका दायर की है। फिर भी 2006 के वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act or the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act ने आदिवासियों/जनजातियों को उस भूमि पर रहने और उसकी रक्षा करने का अधिकार दिया, जिन वन सीमाओं के भीतर वे खेती कर रहे थे।

कुख्यात नर्मदा निष्कासन (Narmada Dam Eviction) एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 12 दिसंबर 1972 को, व्यापक विरोध के बावजूद, भारत सरकार ने नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बाँध (Sardar Sarovar Dam) की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लिया– और 30 प्रमुख, 135 मध्यम और 3000 छोटे बाँध बनाए। घोषणा के अनुसार, इससे क्षेत्र में लगभग 40 मिलियन लोगों को सिंचाई और बिजली के साथ पानी मिलेगा। इसे प्राप्त करने के लिए, 200,000 लोग विस्थापित हुए, जिनमें से अधिकांश आदिवासी/जनजाति थे। एक अन्य उदाहरण में, 2014 में कान्हा टाइगर रिजर्व (Kanha Tiger Reserve) में बैगा और गोंड (Baiga and Gond) समुदायों के लगभग 450 परिवारों को बाघों की रक्षा का हवाला देते हुए निकाला गया। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कर्नाटक में थटकोला और सरगोडु वन रिजर्व (Thatkola and Sargodu Forest Reserve) से 148 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया गया और 156 परिवारों को निकाला गया। साथ ही असम में, बोडो, राभा और मिशिंग या मिरी (Bodo, Rabha and Mishing or Miri) आदिवासी समुदायों के 1000 से अधिक लोगों को उसी वर्ष ऑरेंज नेशनल पार्क (Orange National Park) से निकाला गया (मोहंती-Mohanty, 2019)।

हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (Housing and Land Rights Network) द्वारा 2018 में किए गए शोध के अनुसार, ''अधिकांश कथित बेदखली के मामलों में, राज्य के अधिकारियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।'' शोध से यह भी पता चला कि बलपूर्वक निष्कासन के सभी मामलों के अनेक परिणाम होते हैं । प्रायः सकल मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है।'' भारत मे आदिवासी लोगों के साथ जो हुआ है, वह पूरे विश्व में भी हो रहा है। इस संदर्भ में, एक केंद्रीय अफ्रीकी देश, कैमरून (Cameroon) में आदिवासियों की स्थिति इस तथ्य के बावजूद भी संतोषजनक नहीं है कि देश कें मूल निवासियो के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा 'UN Declaration on the Rights of Indigenous People' के हस्ताक्षर किए हुए हैं। चाड–कैमरून पाइपलाइन परियोजना (The Chad-Cameroon Pipeline Project) ने सैकड़ों हजारों आदिवासी समुदायों को असुरक्षित रूप से प्रभावित किया है। यह परियोजना सांस्कृतिक स्थलों के बलपूर्वक विस्थापन और विनाश का उत्कृष्ट उदाहरण है (*Ibid.*)।

यह न्याय की संपूर्ण उपहासात्मक धटना है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के नाम पर सबसे छोटे पारिस्थितिक पदचिह्नों (Carbon Footprints) वाले मूल वन–निवास समुदायों को उनके घर से निकाल दिया जाता है। इसके बावजूद आदिवासी लोग जंगलों के संरक्षण में सहायता करते हैं। वन अधिकार अधिनियम या अनुसूचित जनजाती व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की पहचान अधिनियम, 2006) (Forests Rights Act or Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest

Rights Act, 2006) के कार्यान्वयन की सही निगरानी जरुरी है। पर्यावरणीय न्याय का मतलब विकास व आदिवासी लोगों के अधिकारों में तालमेल लाना है।

बोध प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. आप पारिस्थितिक न्याय से क्या समझते हैं ? इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. ऐसे उदहारण दीजिए, जहाँ आदिवासीयों के अधिकारों का उलंधन हुआ है।

.....

.....

.....

.....

12.3 पर्यावरणीय सरंक्षण के लिए मूल निवासियों का महत्व

जबकि मूल निवासियो को काम के विश्व में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब भी उनका पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरणीय विचारों के प्रति संवेदनशील है। आदिवासी लोग कई प्रकार की वनस्पती का संरक्षण करते हैं, क्योंकि वे अपने धार्मिक विश्वास के कारण यह मानते हैं कि इनमें देवी–देवताओं का वास है। इस आदिवासी संस्कृति की झलक हमें आदिवासी क्षेत्र जैसे मध्य प्रदेश के डिंडोरी, बालाघाट, व मांडला (Dindori, Balaghat and Mandala) जिलों और छतिसगड. के कर्वधा व बिलासपुर (Kawardha and Bilaspur) जिलों में देखी जा सकती है। आदिवासी पेड़ों व फूलों की भी पूजा करतें हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि इनमें देवी–देवताओं का वास है।

कुछ बिंदुओं पर नीचे चर्चा की गई हैः

- **पौधों और जीवजंतु के संरक्षण में सहायता करना (Conserving Plants and Fauna)**

  मूल निवासी कई पौधों और कृषि संबंधित फसलों जैसे चावल, मक्का, बाजरा, अनाज, फलियां, फल और सब्जियों का संरक्षण करते हैं, जो भारत के उत्तर–पूर्व, मध्य और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विविध कृषि–पारिस्थितिक जलवायु के तहत उत्पन्न हुए हैं। उदाहरण के लिए, भारत के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में कुर्चिया, परियार, खासी, जतिन और गारो (Kurichya, Pariyar, Khasi, Jatin and Garo) जनजातियों द्वारा चावल की कुछ स्थानीय किस्मों जैसे पट्टांबी, चंपारा, वलसाना (Pattambi, Champara, Valsana) का संरक्षण किया जाता है। ये किस्में सुगंधित, अनाज की गुणवत्ता, प्रोटीन सामग्री, पाचन–शक्ति (Aroma, Grain Quality, Protein Content, Digestibility) जैसी विशेषताओं वाले चावल की किस्मों की, की गई खेती की तुलना में आनुवांशिक रूप से बेहतर हैं और कीड़ों, कीटो और रोगों के प्रतिरोध में भी पाई जाती हैं। इन किस्मों को अब चावल प्रजनकों (Rice breeders) द्वारा

कई गुणा किया जाता है और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक (Central Rice Research Institute, Cuttack) में और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलिप्स, मनीला (International Rice Research Institute Phillipines, Manila) को अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार कार्यक्रम (All India Coordinated Rice Improvement Programme) में शामिल किया जाता है।

- **विलुप्तप्रायः प्रजातियों का संरक्षण (Conserving Endangered Species)**

  जनजातियां जंगल के जानवरों के साथ समरसत्ता में रहती हैं और साथ ही प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी जानी जाती है। उदाहरण के लिए, उड़ीसा के गजंम (Ganjam) जिले में समुदाय के नेतृत्व में काला हिरन (Blackbuck) के संरक्षण की पहल में 1990 में लगभग 573 के करीब कम जनसंख्या के क्षेत्र में काला हिरन की संख्या में वृद्धि हुई। 2018 में जनगणना के अनुसार, अनुमानित वृद्धि 4,044 पहुंच गई। यह स्थानीय समुदाय के संरक्षण प्रयासों के कारण हुआ। एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण दक्षिण भारत में बिलीगिरीगंना हिल्स टाइगर रिजर्व (Biligirirangana Hills Tiger Reserve) है, जहां सोलीगा आदिवासी समुदाय (Soliga Tribal Communities) रहते हैं। बताया गया है कि इन समुदायों की उपस्थिति के कारण राष्ट्रीय औसत से कही अधिक बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है।

  हालांकि, नीति निर्माता शायद ही कभी इन स्वदेशी लोगों की कीमत और मूल्य को पहचानते हो। बांधो, खनन इत्यादि के निर्माण के आधार पर किए गए निष्कासन उन स्वदेशी लोगों को विस्थापित कर देते हैं, जो रातों–रात शरणार्थी बन जाते हैं। एक बार आत्मनिर्भर होने के पश्चात, वे आजीविका से वंचित हो जाते हैं। यह उन्हें गरीबी और गरीब ही रहने की स्थिति में धकेल देता है। आदिवासी जब अपने जंगलों से निष्कासित होते हैं, तो उन्हें मुख्यधारा विषयक समाज के हाशिये पर धकेल दिया जाता है। इन लोगों को शोचनीय जीवन स्थिति में अपने नए पड़ोसियों से नाराजगी का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप संघर्ष और तनाव होता है।

बोध प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए।

1. मूल निवासियों की पर्यावरण रक्षा में भूमिका की चर्चा कीजिए ।

.....

.....

.....

.....

12.4 निष्कर्ष

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षित रखने में आदिवासी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनजातीय लोगों की निम्न–कार्बन–फुटप्रिंट जीवन शैली ने हजारों वर्षों के लिए वैश्विक पर्यावरण को संरक्षित कर दिया है, और जलवायु परिवर्तन को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए उनके ज्ञान और सतत तरीकों को मान्यता दी जानी चाहिए, उन्हें अपनाया जाना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके विपरीत, उन्हें सामान्य–तौर

पर राष्ट्रीय और उप–राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं से बाहर रखा गया है। यह आदिवासी लोगों के परामर्श की कमी और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी न होने के कारण हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं में राष्ट्रीय विकास राजनीतियां और नीतियां शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन के तरीकों को प्रभावित करती हैं। इसी समय, कई देशों में लोक नीतियां इस समुदाय की जरूरतों पर प्रत्यक्ष ध्यान या लक्षित ध्यान नहीं देती है, जिसके परिणामस्वरूप, वे आर्थिक विकास के लाभों को पर्याप्त रूप से साझा नहीं कर पाए हैं, जो असमानताओं को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभातें है। इस प्रकार, यह उच्च समय है, जब सरकारों और संरक्षण–आधारित संगठनों ने स्थानीय जैव–विविधता की समृद्धि के संरक्षण, सुरक्षित रखने और सुरक्षा में आदिवासी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना शुरू कर दिया है।

12.5 शब्दावली

पर्यावरणीय न्याय (Environmental Justice): पर्यावरण नीतियों और कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में सभी लोगों का स्पष्ट व्यवहार और सहायक भागीदारी। यह भागीदारी नस्ल, जाति, रंग, आय और जन्म स्थान के किसी भी भेदभाव के बिना होती है।

मूल/स्वदेशी निवासी (Indigenous People): जैसा कि इन्हें पहले से ही मूल निवासियों, आदिवासी या जनजाति लोगों के रूप में जाना जाता है, ये दरसल जातीय समूह हैं, जो एक विशेष स्थान के मूल निवासी हैं। ये ऐसे लोग हैं, जो किसी दिए गए क्षेत्र से जुड़ी परंपराओं, भाषा, रीति–रिवाजों और पहले की युग की संस्कृति को बनाए रखते हैं।

अनुसूचित जनजाती व अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की पहचान अधिनियम, 2006) The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act, 2006): ये कई नामों से जाना जाता है, जैसे वन अधिकार अधिनियम, जनजाती अधिनियम, जनजाती बिल, जनजाती अधिकार अधिनियम। ये वन निवासियों के भूमी व वन संसाधनों पर अधिकारों से सबंधित है। इसका उद्येश्य आदिवासियों या मूल निवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करना है।

12.6 संदर्भ लेख

Mohanty, A. (2019, May 7). Tribal Communities Suffer when Evicted in the Name of Conservation. Retrieved from https://www.downtoearth.org.in /blog/forests/tribal-communities-suffer-when-evicted-in-the-name-of-conservation-64376.

Pattasingh, T. & Paliwal, G. (2014). Tribal Population in India: Regional Dimensions & Imperatives. *Journal of Regional Development and Planning*. 3(2), 28-36.

Thekaekara, M.M. (2019). A Huge Land Grab is threatening India's Tribal People. https://justchangeindia.com/2019/03/18/a-huge-land-grab-is-Threatening-indias-tribal-people/

12.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहिये:**
   - पर्यावरणीय वस्तुओं का उचित विवरण, वितरण और नुकसान;

- निर्णय–निर्माण और वितरण में मानव और गैर–मानव हितो की पहचान।
- विचारात्मक और लोकतांत्रिक भागीदारी का अस्तित्व।
- व्यक्तियों, समूहों और प्रकृति के गैर–मानवीय भागों के बीच क्षमताओं का निर्माण।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**

- जंगल को सुरक्षित रखने में आदिवासियों की रूचि है, क्योंकि यह उनकी जीवन–समर्थन प्रणाली है।
- आदिवासी लोग वनों के संरक्षण में सहायता करते हैं।
- उन्हें प्रत्येक विकासात्मक परियोजना जैसे नर्मदा–बांध निर्माण से विस्थापित किया जा रहा है।
- यह न्याय की संपूर्ण उपहासात्मक रचना है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के नाम पर सबसे छोटे पारिस्थितिक पदचिह्न वाले समुदायों को उनके घर से निकाल दिया जाता है।

बोध प्रश्न 2

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**

- पौधों के संरक्षण में सहायता करना।
- खतरे में प्रजातियों के संरक्षण में सहायता करना।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

इकाई 13 संसाधन उत्पत्ति और क्षमता वृद्धि के वैकल्पिक तरीके*

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 प्रस्तावना

13.2 सतत चयन की प्रासंगिकता

13.3 वैकल्पिक संसाधन उपयोग के पर्यावरणीय लाभ

13.4 निष्कर्ष

13.5 शब्दावली

13.6 संदर्भ लेख

13.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

13.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित बाते समझ सकेंगेः

- सतत पर्यावरणीय विकल्पों की प्रासंगिकता; और
- दुर्लभ संसाधनों की सुरक्षा के लाभ।

13.1 प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र ने बदलती जीवन शैली, तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जीवन जीने के तरीको के लिए पर्यावरण के परिणामों पर विचार किए बिना अपने देशों को विकसित करने की कोशिश में नई चुनौतियों के लिए तैयारी की है। अधिक से अधिक कारखानों को लगातार स्थापित किया जा रहा हैं और हानिकारक रसायनों और सामग्रियों का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जा रहा है (जलील-Jalil, *et al*., 2013)। समय के साथ, शहरी आबादी में कई गुना वृद्धि हुई है। प्राथमिक ऊर्जा की खपत बढ़ गई है और कृषि में रसायनों, उर्वरकों आदि का उपयोग बढ़ गया हैं। ये सभी परिवर्तन पृथ्वी को 'नए राज्य' में परिवर्तित कर रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए कम सत्कारशील (Hospitable) बन रहा है। (मिलमैन-Milman, 2015)

इन सभी खपतों के कारण पर्यावरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। वस्तुओं का अत्याअधिक उत्पादन, जिनमें से कई आरामदायक जीवन व्यतीत करने के लिए अनावश्यक है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग कर रहा हैं, अतिरिक्त प्रदूषण पैदा कर रहा हैं, और भारी मात्रा में अपशिष्ट (Waste) पैदा कर रहा हैं। वैश्विक स्तर पर, पर्यावरणीय क्षति के लिए सभी मनुष्य समान रूप से जिम्मेदार नहीं है। विश्व के कुछ हिस्सों में खपत पैटर्न और संसाधन का उपयोग बहुत अधिक है, जबकि अन्य देशों में, उच्च जनसंख्या स्तर के साथ, खपत का स्तर कम है, क्योंकि संपूर्ण जनसंख्या की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा है। विकसित देशों में पारिस्थितिक पदचिह्न, सामान्य रूप से, विकासशील विश्व की तुलना में बहुत गंभीर है। (डोवर्स व बटलर-Dovers & Butler, 2015)

---

* योगदानः डॉ. निवेदिता शर्मा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली

जिस तरह से ये पारिस्थितिक पदचिह्न विश्व को प्रभावित कर रहे हैं, उसे हमारे दैनिक जीवन को देखकर ही समझा जा सकता है। हम अपनी दिनचर्या में टी वी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर (Television, Air Conditioners, Refrigerators) और अन्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन गतिविधियों को करते समय, हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और पारिस्थिति पर पड़ने वाले इसके प्रभाव से अनभिज्ञ है। इन सभी संसाधनों को जोड़कर परिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint) की गणना की जाती है।

सामान्य रूप से, हम अपने संसाधनों की खपत को कम करके और प्रदूषण को कम करके विश्व पर अपने नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। संसाधनों का उपयोग जिन्हें शीघ्रता से पुनः जीवित या उनका पुनः उत्पादन किया जा सकता है, सततता प्राप्त करने का एक तरीका हैं। संसाधन पर्यावरणीय, आर्थिक या सामाजिक हो सकते हैं। सततता प्राप्त करने के लिए, हमें सतत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, और साथ ही सतत विकल्प बनाने की भी आवश्यकता है। सतत विकास का अब प्राथमिक महत्व है, क्योंकि यह भविष्य में विश्व के सीमित संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन की कुंजी है।

13.2 सतत चयन की प्रासंगिकता

हमारे दैनिक जीवन में एक सरल उदाहरण प्लास्टिक का उपयोग है। यह हमारे दैनिक जीवन में इतनी अच्छी तरह से अंतर्निहित है कि हमारी लगभग सभी चीजें प्लास्टिक (Plastic) से बनी है। सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक का रूप प्लास्टिक बैग है। 1970 के दशक में एक दुर्लभ नवीनता, प्लास्टिक शॉपिंग बैग, अब सर्वव्यापी वैश्विक उत्पाद है, जो एक खरब (Trillion) प्रतिवर्ष की दर से निर्मित होता है। वे माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) के शिखर पर ध्रुवीय बर्फ की टोपी के रूप में महासागरों की गहराई में दिखाई दे रहे हैं और कुछ प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियों का निर्माण कर रहे हैं। प्लास्टिक की थैलियों (Plastic Bags) के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि वह वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ाते हैं। प्लास्टिक की थैलियों का न केवल हमारे प्राकृतिक आवास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वे कई जानवरों की मृत्यु का कारण बन रहे हैं, जो गलती से उनका उपभोग कर लेते हैं।

प्लास्टिक बैग नवीकरणीय (Renewable) नहीं होता है और इसे नष्ट करने के लिए आपको पराबैंगनी या अल्ट्रा वायलेट/यूवी किरणों (Ultra Violet or UV Rays) की आवश्यकता होती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। दूसरी ओर पेपर बैग (Paper Bag) पर्यावरण के अनुकूल है और इसका पुनः नवीकरण किया जा सकता है। 1950 के दशक के बाद से, एकल उपयोग प्लास्टिक (Single-use plastics) ने टिकाऊ प्लास्टिक के उत्पादन को पीछे छोड़ दिया है। यह एक वैश्विक बदलाव है। प्लास्टिक का उत्पादन व्यापक रूप से जीवाश्म हाइड्रोकार्बन (Fossil Hydrocarbons) पर निर्भर है, जो गैर–नवीकरणीय संसाधन है। यदि प्लास्टिक उत्पादन में वृद्धि वर्तमान दर पर जारी रहती है, तो 2050 तक प्लास्टिक उद्योग दुनिया के कुल तेल खपत का 20 प्रतिशत हो सकता है।

कहा जाता है कि लोगों ने 1970 के दशक में किराने का सामान और वस्तुएं ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करना शुरू किया और 20वीं सदी की अंतिम तिमाही में ये थैलिया तेजी से लोकप्रिय हो गई। अब तक उत्पादित कुल प्लास्टिक बैगों पर कोई सटीक आंकड़े गंभीर रूप से नहीं बनाए गए हैं, लेकिन आज लगभग एक खरब प्लास्टिक बैगों का उपयोग शांति से विश्व–भर में प्रत्येक वर्ष किया जाता है (मिलर–Miller, 2012)। ये बैग खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों के साथ

बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि वे बहुत सस्ते, मजबूत, हल्के और कार्यात्मक हैं और भोजन और अन्य सामान ले जाने के एक स्वच्छ साधन के रूप में उपयोग होते हैं। हालांकि, प्लास्टिक की थैलियों में सामान ले जाना आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन वे पर्यावरणीय और कृषि भूमि के पतन के लिए जिम्मेदार हैं, जिसने अनावश्यक रूप से पृथ्वी की कीमती संसाधनों का उपयोग किया है, विशेष रूप से पेट्रोलियम का। (सूगी–Sugii, 2008)।

इन निर्वर्त्य (Disposable) प्लास्टिक थैलियों ने अब प्रशांत महासागर जैसे सुदूर क्षेत्रों सहित हर जगह अपना रास्ता खोज लिया है, इस प्रकार न केवल जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा हो रहा है, बल्कि गड्ढों की भराई और कृषि–भूमि, अब हमारे पर्यावरण और कृषि विकास के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं परिणामतः तथाकथित सभ्य वैश्विक समुदाय की दुनिया का बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय पतन होगा। ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें समुद्री शैवाल के साथ मिश्रित प्लास्टिक शीट को गलती से निगलने के कारण लुप्तप्रायः प्रजातियों के बड़े कछुओं का दम घुट गया (जलील–Jalil, *et al*., *op. cit*.)।

प्लास्टिक की थैलियों के लिए कई पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, जैसे जूट बैग, पेपर बैग, बायो डिग्रेडेबल बैग और पुनः उपयोग योग्य बैग (Jute Bags, Paper Bags, Bio-degradable Bags, and Reusable Bags.)। सामान्य रूप से, प्लास्टिक की थैलियों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में जूट के थैले की सिफारिश की जाती है, क्योंकि थैलों को बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनाया जाता है, जो जूट नामक एक प्लांट फाइबर (Plant Fibre) से आता है, जिसमें अधिकतर सैल्यूलोज (Cellulose) होता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है, और पर्यावरण और कृषि पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है।

दैनिक उपयोग के लिए पेपर बैग है, जो बहुत सुविधाजनक है। इसकी पर्यावरण के अनुकूल प्लास्टिक बैग के विकल्प के रूप में सिफारिश की जाती है। पेपर बैग सामान्य रूप से लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो इन बैगों को नए कागज जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या पुस्तकों में परिवर्तित किया जा सकता है। अपशिष्ट कागज (Waste Paper) भी बायोडिग्रेडेबल (Biodegradable) होते है, ताकि वे आसानी से विक्रत (Degenerate) हो सके और फेंकने वाले स्थानों पर ढेर ना हों। पेपर बैग सामान्य रूप से मॉल और प्रदर्शनियों में बड़े पैमाने पर उत्पादों के वितरण में उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि अनुसंधान से पता चलता है कि पेपर बैग में कम से कम 35 प्रतिशत पुनःनवीकरणीय सामग्री होती है। निगम आजकल प्रचार, सेमिनार, उत्पाद पैकेजिंग और ब्रेंडिंग (Promotions, Seminars, Product Packaging, and Branding) के उद्देश्यों के लिए पेपर बैग का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे प्रतिस्पर्धी है। पुरानी धारणा कि कागज का अर्थ है वनों की कटाई के विपरीत, आज कागज और कागज के बैग बड़े पैमाने पर वृक्ष से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल चीज़ो से बनाए जाते हैं। जैसेः

गन्ने का कचरा–बगासे (Sugarcane Waste -Bagasse): आज कागज का निर्माण गन्ने से निकलने वाले गूदे के कचरे से किया जाता है।

घास (Straw): हां, कागज को भूसे के रेशो से भी बनाया जा सकता है और यदि इसे ग्रामीण भारत में प्रभावी ढंग से कार्यन्वित किया जाता है, तो यह किसानों को फसलों को न जलाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, बल्कि उसे एक मूल्य के लिए बेच सकता है।

जूटः रस्सी (Jute Twine): का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले लेखन और विशेष पेपर बनाने के लिए किया जाता है।

नारियल के भूसे (Coconut Husks): इनको आमतौर पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब इसका उपयोग घनी बनावट के साथ कागज बनाने के लिए किया जा रहा है।

हाथी मलमूत्र (Elephant Excreta): हां, आपने सही सुना, यहां तक कि कागज भी अब हाथी के दुम्बाल से निर्मित है। प्रकृति के अनुकूल बैग व्यापक रूप से उन सामग्रियों से बने होते हैं, जो बैक्टीरिया और वायुमंडल में मौजूद अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होने में काफी आसान होते हैं। इसलिए वे सरल रूपों में विघटित होने में बहुत कम समय लेते हैं।

बोध प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए।

1. सतत चयन के महत्व पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

13.3 वैकल्पिक संसाधन उपयोग के पर्यावरणीय लाभ

आइए अब हम पेपर बेग जैसेः वैकल्पिक तकनीक व संसाधन के उपयोग के पर्यावरणीय लाभ पर चर्चा करतें हैंः

बायोडिग्रेडेबल (Biodegradable)

प्रथम, कागज/जूट बैग का कचरा प्लास्टिक की थैलियों के विपरीत, अगले 1000 वर्षों तक पृथ्वी की सतह पर नहीं ठहर रहा है। अगले 1000 से 10,000 वर्षों तक मनुष्य समुद्र के सभी समुद्री जानवरों, नदियों, तालाबों, झीलों को प्लास्टिक प्रदूषण के कारण सम्भवतः खो नहीं सकते या वे ऊपरी मिट्टी में प्लास्टिक के मिश्रण के कारण अधिकांश भूमि की उर्वरता को खोने का कारण नहीं बन सकते हैं– यदि विश्व में परिवर्तन प्लास्टिक से लेकर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग तक हो। वास्तव में, अधिकांश पेपर बैग के कचरे को नष्ट होने में 6 महीने से कम का समय लगता है, और अधिकतर मामलों में, वे वनस्पति के लिए उपजाऊ कचरे को समाप्त कर देते हैं।

पुनर्चक्रणीय (Recyclable)

ये बैग सामान्य रूप से 100 प्रतिशत पुनः उपयोग करने योग्य होते हैं। पुनरावृति प्रक्रिया के दौरान वातावरण में अत्यंत विषालु और जहरीली गैसों का उत्सर्जन करने वाले प्लास्टिक के विपरीत, कागज/जूट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में ऐसा कोई खतरा नहीं है। इन थैलियों का पुनः उपयोग किया जा सकता है, और कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है।

उर्जा रक्षक (Energy Saver)

कागज और जूट बैग का उपयोग करने के अनेक फ़ायदे होने के अतिरिक्त इसका पर्यावरण के अनुकूल होने का एक कारण यह है कि यह विशाल मात्रा में ऊर्जा को बचाने में सहायता करता है। यह अक्सर स्थानीय संसाधनों से बनतें हैं, जो परिवहन लागत बचाते हैं व अतः ऊर्जा बचाते हैं।

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षक (Conserver of Natural Resources)

ऐसे थैलों पर भारी परिवर्तन करके हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेंगे, क्योंकि ये पुनः चक्रणीय, पुनः प्रयोज्य और बायो–डिग्रेडेबल (Recyclable, Reusable and Bio-degradable) हैं। निष्कर्ष में, यह कहा जाएगा कि अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी ग्रह को बचाने के लिए अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, इको–फ्रेंडली बैग (Eco-friendly Bag) के उपयोग की ओर बढ़ना आवश्यक है।

एक और उदाहरण कोयला और पेट्रोलियम का है. औद्योगिक क्रांति के पश्चात से, मानव की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा के उपयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई है, यह ऊर्जा मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम से आती है। विश्व की अधिकांश ऊर्जा सैकड़ों लाखों वर्ष पहले से निर्मित सामग्री से आती है और इसके लिए पर्यावरणीय परिणाम हैं।

तलछट और चट्टान की परतों के नीचे दबे हुए पौधों और अन्य जीवो के सड़ते अवशेषों (Decomposing Plants and other Organisms, buried beneath layers of Sediment and Rock) को कार्बन युक्त होने के लिए हजारों वर्ष लग गए, जिसे अब जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) कहते हैं। ये गैर–नवीकरणीय ईंधन, जिसमें कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है, विश्व की लगभग 80 प्रतिशत ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं। वे बिजली, गर्मी और परिवहन प्रदान करते हैं, जबकि स्टील से प्लास्टिक तक उत्पादों की एक विशाल श्रंखला बनाने वाली प्रक्रियाओं को भी पोषित करते हैं। जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों (Carbon dioxide and other Greenhouse Gases) का उत्सर्जन करते हैं, जो हमारे वातावरण में गर्मी के जाल को बढ़ाते हैं, जिससे वे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन (Global Warming and Climate Change) में प्राथमिक योगदान देते हैं।

विश्व भर की सरकारें अब जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में लगी हुई हैं। हालांकि, कुछ सरल जीवनशैली में परिवर्तन हमारे दैनिक ऊर्जा खपत में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। उदाहरण के लिएः

- निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक या लोक परिवहन या पैदल चलना या साइकिल चलाना;
- अपने घरों/कार्यालयों में एल ई डी (LED) बल्बो का उपयोग करना; व
- लिफ्टों का उपयोग करने की अपेक्षा सीढ़ियां चढ़ना।

बोध प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए।

1. वैकल्पिक संसाधन उपयोग के विभिन्न तरीको पर चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

13.4 निष्कर्ष

संक्षेप में, दुर्लभ संसाधन और मानव आवश्यकताओं का तेजी से बढ़ना पर्यावरण को संकट में डाल रहा है। हमारी सुविधा के लिए लाई गई जीवनशैली में पहले के परिवर्तन हमें ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय गिरावट के रूप में एक बड़े संकट में डाल रहे हैं। समय की आवश्यकता है कि पर्यावरणीय विकल्पों की ओर जाके अर्थात भारी परिवर्तन करके अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाया जाए। इस तरह हम अपने ग्रह और उस पर जीवन के रूपों को बचा सकते हैं। इस इकाई ने आपका ध्यान पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए वैकल्पिक संसाधन उपयोग की आवश्यकता पर दिया।

13.5 शब्दावली

बायो–डिग्रेडेबल (Bio-degradable): कोई भी पदार्थ, जो बैक्टीरिया या कवक जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा टूटते या विघटित होते हैं। इस तरह के पदार्थों को वातावरण में आसानी से सम्मिलित किया जा सकता है। संक्षेप में जो प्राकृतिक रूप से पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाए ताकि पर्यावरण को हानि ना हो।

कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint): यह ग्रीनहाउस गैसों की कुल मात्रा है, जैसे–कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, जो व्यक्ति, घटना, संगठन, सेवा या उत्पाद के कारण बनती है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में व्यक्त किया जाता है।

पराबैंगनी किरणें (Ultraviolet Rays): यह 10 की तरंग दैर्ध्य के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण (Electromagnetic Radiation) का एक रूप है, जिसकी आवृति 30 PHz (Petahertz) से 750 THz (Terahertz) तक होती है, जो दृश्य प्रकाश की तुलना में कम लेकिन किरणों से अधिक लंबा होता है। यह सूर्य से निकलने वाले कुल विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पादन का लगभग 10 प्रतिशत है।

13.6 संदर्भ लेख

Dovers & Butler (2015). Population and Environment: A Global Challenge. Retrieved from https://www.science.org.au/curious/earth-environment/population-environment.

Jalil, M. A., Mian, N. & Rahman, M. K. (2013). Using Plastic Bags and its Damaging Impact on Environment and Agriculture: An Alternate Proposal. *International Journal of Learning & Development.* 3(4), 1-14.

Miller, R.M. (2012). Plastic Shopping Bags: An Analysis of Policy Instruments for Plastic Bag Reduction. Retrieved from http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/253904.

Milman, O. (2015). Rate of Environmental Degradation puts Life on Earth at Risk, say scientist. The Guardian. Retrieved from https://www.theguardian.com/environment/2015/jan/15/rate-of-environmental-degradation-puts-life-on-earth-at-risk-say-scientists.

Sugii, T. (2008). Plastic Bag Reduction: Policies to Reduce Environmental Impact. U.S. Proquest.

13.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः

- प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल और बायो–डिग्रेडेबल नहीं है।
- प्लास्टिक की थैलियों के लिए कई पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, जैसे–जूट बैग, पेपर बैग, बायो–डिग्रेडेबल बैग, और पुनः उपयोग योग्य बैग।
- सामान्य रूप से, प्लास्टिक बैग के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में जूट बैग की सिफारिश की जाती है।
- दैनिक उपयोग के लिए एक और बहुत सुविधाजनक पेपर बैग है, जिस की प्लास्टिक बैग के स्थान पर एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में भी सिफारिश की जाती है।
- गन्ने के कचरे को अपशिष्ट गूद्दे से निर्मित किया जाता है, जिसे गन्ने से चीनी बनाने के बाद छोड़ दिया जाता है और यह पर्यावरण के अनुकूल है।
- घास, जूट, नारियल और हाथी का मलमूत्र वातावरण में विद्यमान बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों द्वारा विघटित होने में बहुत आसान है। इसलिए, वे पर्यावरण के अनुकूल है।

बोध प्रश्न 2

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः

- बायो–डिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना।
- पुनर्चक्रणीय सामग्री पर ध्यान देना।
- ऊर्जा बचत–कर्ताओं का अधिक उपयोग करना।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

इकाई 14 सतत् विकास में गैर–राज्य हितधारकों की भूमिका*

इकाई की रूपरेखा

14.0 उद्देश्य

14.1 प्रस्तावना

14.2 सतत् विकास की आवश्यकता

14.3 सतत् विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

14.4 सतत् विकास में श्रमिक संघों की भूमिका

14.5 सतत् विकास में निगमों की भूमिका

14.6 सतत् विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका

14.7 निष्कर्ष

14.8 संदर्भ लेख

14.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

14.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित बाते समझ सकेंगे :

- सतत् विकास का अर्थ और स्वरूप;
- सतत् विकास की प्रासंगिकता; तथा
- सतत् विकास में विभिन्न हितधारकों की भूमिका।

14.1 प्रस्तावना

सतत् विकास शब्द 1980 के दशक के मध्य में निर्मित किया गया था। हालाँकि इसके आरंभ से ही इसकी अवधारणा निरंतर बदल रही है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में अधिक गतिशील और निरंतर परिवर्ती शासन संरचनाओं में नीति रचना और कार्यान्वयन में गैर–राज्य कार्यकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण नीति–निर्माण में नागरिकों की भागीदारी की मांग में वृद्धि हुई है। पर्यावरण और सततता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर–सरकारी संगठनों (Non-governmental Organisations-NGOs-एन जी ओ) की संख्या में भी वृद्धि हुई है। हाल के शोध से पता चलता है कि नागरिक समाज संगठन, अपने दम पर और अंतरराष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने वाले (Transnational Citizens' Networks) के दम पर वैश्विक नीति एजेंडा को आकार देने, सरकारों, नागरिकों और उद्योगों को शिक्षित करने और सबसे ऊपर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण शासन को मज़बूत बनाने में सक्षम है।

सतत् विकास के लिए एक परिवर्ती तारक (Variable) की अपेक्षा अधिकतम लाभ अनुकूलन अनेक परिवर्ती तारकों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए सरकारी विभागों की आवश्यकता होती है, जो एक साथ बहु–अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में, एक साथ काम करने के लिए या कुछ मामलों में, क्षेत्रीय सम्मेलन द्वारा आयोजित

* योगदानः डॉ. निवेदिता शर्मा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली।

किए जाते हैं। इस संयुक्त योजना के लिए, कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समन्वय की आवश्यकता है। समाज में उपलब्ध कौशल की अधिकता को नागरिक समाज के संस्थाओं जैसे– एन जी ओ, निजी निकायों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, श्रमिक संघ आदि की सम्मिलित भागीदारी को उपयोग में लाना चाहिए, जिन्हें योजना का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए और सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals-SDGs-एस डी जी) के लिए कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

14.2 सतत् विकास की आवश्यकता

एक विकसित धारणा है कि केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है : किसी भी कार्रवाई के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू परस्पर जुड़े हुए हैं। एक समय में, इनमें से केवल एक पर विचार करने से निर्णय में त्रुटियां हो सकती हैं और 'अरक्षणीय' परिणाम सामने आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, इतिहास गवाह है, केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने से, उन सामाजिक और पर्यावरणीय हानियों को जन्म दिया है, जिन्होंने आगे जाकर समाज को प्रभावित किया है। इसी संकेत के माध्यम से, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए और लोगों को जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें प्रदान किया जाए, जो कम से कम आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करती है (स्ट्रेंज एंड बेले - Strange & Bayley, 2008)।

इस तथ्य की वास्तविकता यह है कि हम उन परिस्थितिक तंत्रों और सेवाओं पर निर्भर करते हैं, जो हमें वो प्रदान करते हैं, जिनसे हम कार्य करते हैं जैसे, व्यवसाय चलाते हैं, समुदायों का निर्माण करते हैं, हमारी जनता का पोषण करते है, और इससे भी अधिक। क्या हम अधिक स्पष्ट, वर्तमान संबंधी महत्त्वपूर्ण उदाहरणों पर विचार करते हैं – मिट्टी की आवश्यकता, जो भोजन उत्पन्न कर सकती है या पीने के लिए स्वच्छ पानी या कम स्पष्ट लेकिन समान रूप से महत्त्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) के दौरान ऑक्सीजन उत्पादन या बैक्टीरियल अपघटकों (Bacterial Decomposers) के द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण। हम इस निष्कर्ष से बच नहीं सकते हैं कि हम अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं। यदि हम इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए पर्यावरण की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं या नष्ट करते हैं, तो हमें ऐसे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके लिए हम पूरी तरह से तैयार नहीं है।

उसी तरह, समाजों की दीर्घकालिक सततता और सफलता एक स्वस्थ और उत्पादक जनसंख्या पर निर्भर करती है। एक समाज (या बड़े समाज के भीतर के समुदाय) जो अशांति, गरीबी ओर बीमारी का सामना करते हैं, वे दीर्घकालिक विकसित नहीं होंगेः सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण एक–दूसरे के विकास से संबंधित है और समस्त प्रणाली एक स्वस्थ जीव मंडल पर निर्भर करती है, जिसमें हम रहते हैं।

इसलिए, समाज को दृढ़ बनाने के लिए सतत् विकास एक कठिन विषय है, क्योंकि इसमें मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस विषय की परिभाषा और जटिलता के कारण, इसको सरलता से समझने में सक्षम होने के लिए इसके महत्त्व को समग्र रूप से जांचना सबसे उत्तम है। जनसंख्या, सतत् विकास अभियान चलाने वाला मुख्य कारक है। इसलिए सतत् विकास के महत्त्व को इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है।

आवश्यक ज़रूरतें प्रदान करना (Provision of essential human needs)

जनसंख्या के विस्फोट (Explosion of population) का अर्थ है कि लोगों को सीमित जीवन के लिए भोजन, आश्रय और पानी जैसी आवश्यक चीज़ों के लिए जूझना पड़ेगा। इन मूलभूत ज़रूरतों की पर्याप्त व्यवस्था लगभग पूरी तरह से मूलभूत ढांचे पर टिकी हुई है, जो उन्हें लंबे समय तक संभालने योग्य है। उदाहरण के लिए, यदि सरकारें

नवीकरणीय और सतत विकल्पों के स्थान पर ऊर्जा के जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों का उपयोग करने पर ज़ोर देती है, तो इन मूलभूत ज़रूरतों की आपूर्ति की लागत और पर्यावरणीय प्रभाव से यह एक कठिन काम बन जाएगा।

कृषि आवश्यकताएं (Agricultural requirements)

बढ़ती जनसंख्या का अर्थ है कि कृषि–क्षेत्र को मज़बूत करना होगा। 3 अरब से अधिक लोगों को खिलाने के तरीके ढूंढ़ना हमें विचलित कर सकता है। यदि भविष्य में इसी तरह की खेती, रोपण, सिंचाई छिड़काव और कटाई की तकनीकों का उपयोग किया गया, तो वे जीवाश्म ईंधन संसाधनों को चलाने के लिए अनुमानित आर्थिक रूप से बोझिल साबित हो सकते हैं। सतत् विकास मिट्टी (Soil) की अखंडता को बनाए रखते हुए उच्च पैदावार को बढ़वा देने के लिए प्रभावी कृषि तकनीकों और फसल रोटेशन (Rotation, पूर्णतः चक्रानुक्रम) जैसी सतत कृषि विधियों पर केंद्रित है, जो एक विशाल जनसंख्या के लिए भोजन का उत्पादन करती है।

जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करना (Manage climate change)

जलवायु परिवर्तन को सतत विकास कार्यों द्वारा कम किया जा सकता है। सतत विकास कार्यों में तेल, प्राकृतिक गैस और कोयला जैसे ईंधन के जीवाश्म आधारिकत स्रोतों के उपयोग को कम करना है। ऊर्जा के जीवाश्म ईंधन स्रोत असतत हैं, क्योंकि वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे और ग्रीन हाउस गैसों के फैलाव के लिए जिम्मेदार होंगे।

वित्तीय स्थिरता कायम करना (Establish fiinancial stability)

सतत् विकास कार्यों से दुनिया भर में अधिक आर्थिक रूप से स्थायी अर्थव्यवस्था बनाने की क्षमता है। विकासशील देश, जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं कर सकते, वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति देने के लिए ऊर्जा के नवीकरणीय रूपों का लाभ उठा सकते है। नवीनकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास से, ये देश जीवाश्म ईंधन प्रौद्योगिकियों के आधार पर सीमित नौकरियों के विपरीत स्थायी रोज़गार उत्पन्न कर सकते हैं।

जैव–विविधता की सतत्तता (Sustenance of biodiversity)

असतत विकास ओर अति उपभोग, सेवन जैव–विविधता को बहुत प्रभावित करते हैं। जीवन परिस्थितिकी तंत्र इस तरह से बनाया गया है कि प्रजातियाँ जीवित रहने के लिए एक–दूसरे पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, पौधे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो मनुष्यों के श्वसन के लिए आवश्यक है। मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जो पौधों के विकास और उत्पादन के लिए आवश्यक है। वायु मंडल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन जैसे असतत विकास कार्यों से कई पौधों की प्रजातियों की मृत्यु हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वायुमंडलीय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यह मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है। सतत् विकास कार्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों और जैविक खेती प्रथाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जो वातावरण में किसी भी ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करते।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आधुनिक साहित्य ने इस विचार को स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि वैश्विक क्षेत्र में निर्णय लेना अब केवल राज्यों का विशेषाधिकार या जिम्मेदारी नही है। पारंपरिक राज्य–केंद्रित सिद्धांतों को चुनौती दी गई है और तेज़ी से, शोधकर्ताओं को एक नई वैश्विक शासन प्रणाली में गैर–राज्य अभिनेताओं (हितधारकों) की भूमिका में रुचि हुई है।

12.3 सतत् विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका

गैर–सरकारी संगठन (एन जी ओ) और अन्य सभ्य सामाजिक समूह न केवल शासन के हितधारक हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए सार्वजनिक/लोक समर्थन के सक्रिय

संग्रहण के माध्यम से अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। वैश्विक शासन में सभ्य समाज की भागीदारी में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हो रही है। एन जी ओ आंदोलन ने विभिन्न तरीकों से विकास के विभिन्न मॉडलों/प्रतिमानों पर प्रतिक्रिया दी है : कुछ एन जी ओ ने आर्थिक परियोजनाओं को लागू किया है। कुछ संसाधन विकास पहल के सामाजिक प्रभाव की निगरानी करते हैं, अन्य पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी करते हैं। कुछ राहत और सामाजिक कल्याण सेवाओं का वितरण करते है। कुछ क्षेत्रों या समुदायों को व्यवस्थित करने में सहायता करते है। इसके अतिरिक्त, कुछ गैर–सरकारी संगठन है, जो कीटनाशकों के उपयोग कर और अन्य हानिकारक रसायन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करते है, उनका विरोध करते हैं। कुछ वैकल्पिक रणनीतियों के विकास का कार्य भी करते हैं। अंत में, कुछ एन जी ओ ऐसे हैं, जो बहु–क्षेत्रीय हैं जो कई मुद्दों पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन सभी सतत विकास प्रक्रिया के कुछ आयामों से संबंधित हैं।

यह माना जाता है कि एन जी ओ की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक बैठकों की तैयारी में उन्हें अनुकूल आधार प्रदान करती है, जहां वे सरकारी एजेंडों को प्रभावित करने वाले सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने में सक्षम (औपचारिक और अनौपचारिक रूप से) प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डालते हैं और आधिकारिक विषय में उत्पादक सामग्री प्रदान करते हैं। जब सही अवसर, समय और स्थान प्रदान किया जाता है तो एन जी ओ वास्तव में अपनी राष्ट्रीय सीमाओं की सीमा के भीतर राज्यों के साथ अंतरंग पारस्परिक विचार–विमर्श कर सकते हैं, जिससे वे राज्यों को प्रभावित करते हैं। अन्यथा बिना पारस्परिक क्रिया के वे ऐसा नहीं कर पाएंगे।

जबकि संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों (Specific International Environmental Agreements) के लिए समुदाय के कई सम्मेलन और बैठकें आयोजित करता है। 1992 का यू एन सी ई डी (United Nations Conference on Environment and Development-UNCED) और सतत् विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit on Sustainable Development WSSD-डब्ल्यू एस एस डी) 2002 को दो आधारशीला सम्मेलन माना जाता है, जो कि सतत् विकास के लेख को आगे बढ़ाते हैं। रियो डी जेनेरो में एन जी ओ की भागीदारी उच्च थी, लेकिन इसने डब्ल्यू एस एस डी में सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। डब्ल्यू एस एस डी के प्रस्तावों की भाषा में सरकार–नागरिक समाज की भागीदारी पर जोर, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था, जिसे विषय के रूप में देखा गया।

एन जी ओ ने वर्षों से सरकार के सामाजिक–आर्थिक विकास के एजेंडें पर प्रतिक्रिया दी है। इस प्रकार, जब सरकार ने पूंजी–उन्मुख विकास से ध्यान परिवर्तन कर गरीबी–विरोधी कार्यक्रमों पर जोर दिया, तो गैर–सरकारी संगठनों ने कल्याण और सेवा वितरण हस्तक्षेपों से पृथक् होकर गरीबी पर प्रत्यक्ष वार किया। इसके पश्चात् 1990 के दशक में, जब राज्य वृहद् आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों की ओर अग्रसर हुआ, एन जी ओ ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाने पर ध्यान देना शुरू किया। इसने राज्य के साथ नवीन तरीकों को विकसित करने और नीति में अनुरूप परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ काम किया। उन्होंने वकालत और पैरवी भी की, नेटवर्किंग को बढ़ाया, अपने संचालन की सीमा का विस्तार किया और हाशिए के समूहों को लक्षित किया। राज्य और गैर–सरकारी संगठनों के लक्ष्य विशेष रूप से समुदायों को सशक्त बनाने, भागीदारी को प्रोत्साहित करने, लोकतांत्रिक संस्थानों को मज़बूत करने और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के क्षेत्रों में परिवर्तित हुए है।

पर्यावरण के क्षेत्र में एन जी ओ (NGOs working in the area of Environment)

पर्यावरणीय गैर–सरकारी संगठन औद्योगिक और कृषि रसायनों से हवा, पानी और मिट्टी के लिए गंभीर खतरे की प्रतिक्रिया में आए। पर्यावरणीय एन जी ओ आम तौर

पर पर्यावरण से संबंधित कारणों जैसे जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, ओजोन परत की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव–विविधता और भूमि उपयोग, ऊर्जा, संरक्षण, पर्यावरण क्षरण, भूमि पतन जैसे कारणों को उठाते हैं। भारत में काम करने वाले पर्यावरण एन जी ओ के कुछ प्रमुख उदाहरण है– हरित शांति भारत (ग्रीनपीस इंडिया), आवाज़ संस्था, गोवा संस्था, संरक्षण भारत, संरक्षण, पारिस्थितिक सुरक्षा के लिए संस्था, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ भारत और विनरॉक अंतरराष्ट्रीय भारत (Greenpeace India, Awaaz Foundation, Goa Foundation, CARE India, Conserve, Foundation For Ecological Security, WWF India and Winrock International India)।

कई पर्यावरणीय एन जी ओ ने भविष्य के विकास के लिए एक स्थायी संरचना बनाने के लिए सरकार और उद्योग के साथ सहभागिता आरंभ की है। ये संगठन औद्योगिक भवनों और निगमों (Corporates-कारपोरेट्स) को परामर्श प्रदान करते हैं और विकासशील पर्यावरण के अनुकूल और सतत विकास नीतियों पर सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर सक्रिय रूप से संलग्न है। कुछ कंपनियां अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियों (Corporate Social Responsibility-CSR-सी एस आर को लागू करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों के साथ सहयोग कर रही हैं।

पर्यावरणीय एन जी ओ उपलब्ध मुद्दों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए गौण और मुख्य स्रोतों पर भरोसा करते हैं। यह पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्र और राज्य प्रदूषण मंडल द्वारा तैयार की गई सरकारी विवरण के रूप में या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सम्मेलनों और सेमिनार में भाग लेने के माध्यम से हो सकता है। मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और समाचार–पत्र, प्रबल पर्यावरणीय मुद्दों को सामने लाते हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ पर्यावरणीय गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकता है।

ये गैर–सरकारी संगठन प्रश्नावली भरने के माध्यम से मुख्य आंकड़े एकत्र करते हैं, पर्यावरणीय हितधारक जैसे स्थानीय जनसंख्या, उद्योग, सरकारी एजेंसियों, जनता और अन्य के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं। इसके अतिरिक्त, तेज़ी से, पर्यावरणीय एन जी ओ सूचना के अधिकार या आर टी आई का उपयोग कर रहे हैं, ताकि सरकार के नियमों और पर्यावरण कानूनों पर अधिनियम संबंधित डेटा, परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी, सरकारी रूपरेखा और अन्य प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सके। उसी से प्राप्त सूचना और निष्कर्षों का विश्लेषण करने के पश्चात् डेटा एकत्रित करने के चरण का पालन किया जाता है। निष्कर्ष और विश्लेषण के आधार पर ये एन जी ओ कुछ निश्चित कार्रवाई करते हैं, जिसके पर्यावरणीय जोखिम को कम करने हेतु अपराधी या पी आई एल (Public Interest Litigation-PIL) के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए आम जनता में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में स्पष्ट जागरूकता का प्रसार कर सकें (सधुं व अरोरा-Sandhu & Arora)।

विकास के क्षेत्र में एन जी ओ (NGOs working in the area of Development)

भारतीय गैर–सरकारी संगठन 100 से अधिक वर्षों से एक प्रकार के या किसी अन्य के विकास कार्य में शामिल हैं और भारत सरकार के कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण रहे हैं, साथ ही साथ 1947 में देश की आज़ादी के पश्चात् से अंतरराष्ट्रीय एन जी ओ दाताओं के साथ भागीदार बन रहे हैं। गैर–सरकारी संगठनों के विकास के लिए, व्यापक अभिलाषी समुदाय उन्हें कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जैसे– गरीबी कम करना, हाशिए को संबोधित करना, सामाजिक न्याय को प्राप्त करना और मानवाधिकारों के लिए सम्मान को बढ़ावा देना। सिद्धार्थ सेन (Siddhartha Sen,1999) ने विकास कार्यों में शामिल भारतीय गैर–सरकारी संगठनों की दो प्रमुख विशेषताओं की पहचान की है। प्रथम, यह

है कि एन जी ओ वित्तीय मध्यस्थता की भमिका निभाते हैं, वे गरीबी के लिए काम करते है और द्वितीय, ये गैर–सरकारी संगठन गैर–प्रतिनिधि संगठन हैं।

यह ऊपर उल्लिखित एन जी ओ की सामान्य चर्चा के अनुरूप है, जबकि एन जी ओ के औपचारिक सदस्यों की संख्या बहुत कम है (आमतौर पर पेशेवर अभिजात वर्ग–Professional Elite)। वे किसी विशेष क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में लोगों की सेवा करते हैं। वे प्रतिनिधि या पारस्परिक लाभ संगठनों की अपेक्षा मुख्य रूप से सार्वजनिक लाभ संगठन है और वे व्यापक सार्वजनिक लाभ के लिए परोपकारी उद्देश्यों से प्रेरित हैं। भारत में विकसित गैर–सरकारी संगठनों को उन संगठनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो सामान्य रूप से मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग के पेशेवरों या अर्ध–पेशेवरों द्वारा बनाए जाते हैं या तो गरीबों के साथ काम करते है या उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं या समुदाय–आधारित या ग्रामीण संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं (सेन- Sen, *ibid.*)।

बोध प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. सतत् विकास की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

2. सतत् विकास में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका क्या है?

.....

.....

.....

.....

14.4 सतत् विकास में श्रमिक संघों की भूमिका

श्रमिक संघ (Trade Unions) किसी भी राष्ट्र में आधुनिक औद्योगिक संबंधों की प्रणाली का एक प्रमुख घटक है, प्रत्येक को अपने संविधान के अनुसार, अपने उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, और प्रत्येक की उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपनी रणनीति होती है। श्रमिक संघ औद्योगिक प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सतत् विकास के बारे में श्रमिक संघ विचार–विमर्श वर्तमान सामाजिक और आर्थिक विकास और श्रमिकों के लिए उनके निहितार्थों पर हमेशा निर्भर करता है।

इतिहास के प्रत्येक भाग में, श्रमिक और उनके समुदाय विकास के असतत उदाहरणों के प्रथम पीड़ितों में से है, चाहे वह नौकरी विस्थापन, समुदाय उथल–पुथल, औद्योगिक पीड़ा या मृत्यु के रूप में हो। वास्तव में, श्रमिक आंदोलन की उत्पत्ति का पता हम अतिदुष्ट कार्य स्थितियों के विरुद्ध श्रमिकों द्वारा की गई सामूहिक कार्रवाई से लगा सकते हैं। (गेरेलुक और रोयर-Gereluk & Royer 2001)।

सतत विकास में श्रमिक संघ की रुचि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के जीवन स्तर और गुणवत्ता दोनों को बेहतर बनाने की इच्छा से उत्पन्न होती है। यह नई व्यापारिक

संस्था नहीं है, बल्कि श्रमिकों और उनके समुदायों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए लंबे अभियानों से स्वाभाविक रूप में विकसित हुआ है। श्रमिक संघ वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सतत् विकास प्रक्रिया के 2030 के एजेंडे में पूर्ण रूप से शामिल हैं। वे संघ की स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं, सामाजिक संवाद और सामूहिक सौदेबाजी की रक्षा करते हैं, और उचित काम, सामाजिक संरक्षण और कामकाजी लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देते है। इस कार्य के माध्यम से, श्रमिक संघ सतत विकास लक्ष्यों या एस डी जी को प्राप्त करने में सहायक होते है। इसी ढाचें में दुनिया भर के श्रमिक संघ राष्ट्रीय निगरानी और विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे उनकी सरकारें सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को प्राप्त करने के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं के संबंध में व्यवहार कर रही है।

श्रमिक संघ के उद्देश्य

- **मज़दूरी ओर वेतन (Wages and Salaries):** मज़दूरी और वेतन श्रमिक संघ का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय है। संगठित उद्योग में मज़दूरी और लक्ष्य सामूहिक सौदेबाजी, वेतन बोर्ड, समझौता और न्यायिक निर्णय जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्धारित किए जाते है। इन सभी प्रक्रियाओं का कार्य व्यवस्थित–जांच के योग्य होता है। संघ शक्ति और वस्तुनिष्ठ तथ्य इन मंचों के माध्यम से मज़दूरी की स्थिति को आशापूर्वक प्रभावित करते हैं।
- **काम करने की स्थितियां (Working Conditions):** श्रमिक संघ का अन्य प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। काम करते समय प्रत्येक कार्यकर्ता को पीने का पानी, न्यूनतम काम के घंटे, भुगतान किए गए अवकाश, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षा उपकरण और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
- **कार्मिक नीतियां (Personnel Policies):** पदोन्नति, स्थानांतरण और प्रशिक्षण के संबंध में मालिकों की किसी भी कार्मिक नीति को श्रमिक संघ द्वारा चुनौती दी जा सकती है, यदि वह मनमानी या एक–पक्षीय हो।
- **अनुशासन (Discipline):** श्रमिक संघ किसी भी कार्यकर्ता के विरुद्ध प्रबंधन द्वारा की गई मनमानी अनुशासनात्मक कार्रवाई से श्रमिकों की रक्षा भी करते है। किसी भी कर्मचारी को प्रबंधन द्वारा मनमाना स्थानांतरण या निलंबन के रूप में पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।
- **कल्याण (Welfare):** श्रमिक संघ का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करना है। इसमें श्रमिक के परिवार के सदस्यों या बच्चो ंका कल्याण शामिल है।
- **कर्मचारी और मालिक के संबंध (Employee and Employer Relations):** औद्योगिक शांति के लिए, मालिक और कर्मचारियों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। लेकिन प्रबंधन की उच्च शक्ति के कारण कभी–कभी इस स्थिति में संघर्ष उत्पन्न होता है। श्रमिक संघ श्रमिकों के समस्त समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रबंधन के साथ बातचीत जारी रखते है।
- **संगठनात्मक स्वास्थ्य और उद्योग के हित की सुरक्षा (Safeguarding organisational health and the interest of the industry):** श्रमिक संघ श्रमिकों को संतुष्टि प्राप्त कराने में भी सहायता करते हैं। श्रमिक संघ औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए प्रक्रिया बनाकर बेहतर औद्योगिक संबंधों में सहायता करते हैं।

भारत में श्रमिक संघ के कार्य (Functions of Trade Unions in India)

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सामूहिक बातचीत को उस तकनीक के रूप में परिभाषित किया है, जिसके द्वारा रोज़गार की शर्तों के अनुसार विवाद को बलप्रयोग के स्थान पर समझौते द्वारा मित्रभाव से हल किया जाता है, और इस प्रक्रिया में मालिक और कर्मचारी के बीच कार्य–स्थितियों के संबंध में बातचीत और चर्चा होती है। सामूहिक भाव–तोल (Collective Bargaining) श्रमिकों के मुद्दों को हल करने में सहायता करता है। सामूहिक भाव–तोल आंदोलन की नीव है और यह श्रमिकों के हित में है कि वैधानिक मान्यता को श्रमिक संघ और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता के लिए स्वीकार किया गया है।
- श्रमिक संघ मज़दूरों को वेतन वृद्धि से सुरक्षित करते हैं ओर शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से नौकरी की सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- श्रमिक संघ हड़ताल या चिकित्सक ज़रूरतों के दौरान श्रमिकों की वित्तीय और गैर–वित्तीय सहायता प्रदान करने में भी सहायक होते हैं।
- समझौता करते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि जो श्रमिक संघ के सदस्य नहीं है, उनके कर्मचारियों के हित भी सुरक्षित होते हैं, और श्रमिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता हैं।

पर्यावरण की नजर से देखे तो श्रमिक संघों का प्रभाव सतत विकास पर अप्रत्यक्ष, परन्तु बहुत महत्वपूर्ण है।

14.5 सतत् विकास में निगमों की भूमिका

निगमीय सततता या निगमीय सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility -CSR-सी एस आर) पिछले कुछ दशकों में एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा बन गई है। यद्यपि यह पश्चिम के विकसित देशों में उत्पन्न हुई थी, लेकिन इस अवधारणा को कई विकासशील देशों में, निगमों और नीति–निर्माण एजेंसियों द्वारा अपनाया और अनुकूलित किया गया है। आश्चर्यजनक रूप से, इन देशों में नीतिगत उद्देश्यों के रूप में वृद्धि और विकास को महत्त्व दिया गया है, जिससे सी एस आर का सतत् विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। यह जिम्मेदारी के बारे में है, जो व्यवसायों की समाज के प्रति है, उनकी कानूनी आवश्यकताओं से परे जाकर है (करों का भुगतान, उनके उत्पादों और सेवाओं को लाभ–उपयोगी बनाना, रोज़गार कानूनों का पालन सुनिश्चित करना आदि (Paying taxes, making sure their products and services 'work', ensuring that they obey employment laws etc.)।

एक कारपोरेट स्तर पर सतत विकास की अवधारणा को सी एस आर के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक मुद्दों जैसे तीनों स्तंभों पर आधारित है। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर ध्यान देना निश्चित रूप से नया नही है, पिछले वर्षों में जलवायु परिवर्तन, गरीबी, मानवाधिकार उल्लंघन और एच आई वी/एड्स (HIV/AIDS) जैसी वैश्विक समस्याओं के दबाव के कारण नवीकृत रूप से दिलचस्पी देखी गई है। फर्मों या निगमों को एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है ओर इस प्रकार, यह सतत् विकास में अधिक योगदान देते हैं। (कोल्क एंड ट्यूलडर-Kolk & Tulder, 2010)।

सी एस आर का अर्थ उन नीतियों को विकसित करने की प्रतिबद्धता है, जो जिम्मेदारी कार्यों को दैनिक व्यावसायिक कार्यों में एकीकृत करती हैं, और इन कार्यों को लागू करने की दिशा में प्रगति पर रिपोर्ट देती है। सामान्य सी एस आर नीतियों में शामिल हैं :

- आंतरिक नियंत्रण सुधार को अपनाना;
- कर्मचारियों को काम पर रखने और भेदभाव को रोकने में विविधिता के लिए प्रतिबद्धता;
- प्रबंधन दल जो कर्मचारियों को लागत की अपेक्षा संपत्ति के रूप में देखते हैं;
- उच्च प्रदर्शन कार्यस्थल, जो निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं में व्यावसायिक कर्मचारियों के विचारों को प्रकीकृत करते हैं;
- संचालन नीतियों को अपनाना, जो सामाजिक और पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन से अधिक है, उन्नत संसाधन उत्पादकता, एक अधिक उत्पादक, कुशल और लाभदायक रूप में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित है, जैसे, पुनर्नवीनीकरण सामग्री और उत्पाद की पुनरावृत्ति करना; और
- उन परिस्थितियों की जिम्मेदारी लेना, जिसके तहत वस्तुओं का उत्पादन प्रत्यक्ष या अनुबंध कर्मचारियों द्वारा देश या विदेश में किया जाता है।

एस डी जी फ्रेमवर्क (SDG Framework) को सरकारों, व्यवसायों, ज्ञान संस्थानों और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयास के रूप में माना जा सकता है, ताकि सतत् विकास को साकार करने के लिए संस्थागत पहल की जा सके। लक्ष्य–आधारित संस्था के रूप में, एस डी जी सतत् विकास के लिए कारपोरेट (निगमों) नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। लक्ष्य एक विशिष्ट, संक्षिप्त, मध्यम श्रेणी का और सतत् विकास के एक नए प्रक्षेप पथ की दिशा में एक साथ कई हितधारकों की गतिविधियों को उन्मुख करने और सामाजिक रूप से गतिमान करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। जबकि साथ ही साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी प्रगति के लिए सहकर्मी एजेंटों पर दबाव डालते हैं। सतत् विकास लक्ष्य (एस डी जी) का नीचे से ऊपर तक का दृष्टिकोण (Bottom-up Approach), जो कई प्रकार के हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। साथ ही, वह व्यवसायों को संघटित करने में भी सहायता करता है।

इसके अतिरिक्त, एस डी जी एक स्वैच्छिक संस्थागत समझौता है और एजेंटों को यह तय करने की स्वतंत्रता है कि वे किन लक्ष्यों की दिशा में काम करना चाहते हैं। साथ ही, कुछ एस डी जी लक्ष्य इतने जटिल हैं कि उन्हें केवल सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है, जिसमें सरकारें, कंपनियाँ और नागरिक समाज संगठन भागीदारी में काम करते हैं (ट्यूलडर व कीन-Tulder & Keen, 2018)।

निगमीय सततता को कंपनी के प्रबंधन कार्यों और बाज़ार में उपस्थिति के द्वारा इसकी क्षमता के रूप में देखा जाता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र (प्राकृतिक संसाधनों में सुधार, प्रदूषण के स्तर को कम करना, आदि), समुदाय (स्थानीय जनता का समर्थन, रोज़गार पैदा करना, आदि) और आर्थिक विकास (उचित मज़दूरी के लगभग भुगतान के माध्यम से वितरण, आदि) पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कंपनी की सततता तब भी हो सकती है, जब वह पर्यावरण, सामाजिक या आर्थिक मुद्दों पर अधिक सकारात्मक और कम नकारात्मक प्रभाव डालकर अपने शेयरधारकों के लिए मूल्य स्थापित करती है।

बड़े पारदेशीय (Transnational) निगमों ने सतत् विकास के मुद्दों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। इससे यह परिवर्तन आया है कि प्रबंधन बोर्ड और अधिकारियों ने अपनी सभी गतिविधियों में सततता के मुद्दों को ध्यान में रखना प्रारंभ कर दिया है। कंपनियों के शेयर और लाभांश की वापसी दर अब केवल एक वस्तु नहीं है, जो प्रबंधकों के लिए मायने रखती है। विभिन्न कारणों से वे सतत् विकास नीति को शामिल करते हैं। आजकल अधिकांश कंपनियों ने एक सी एस आर नीति विकसित की है, और इसे जनता तक पहुँचाने के लिए बहुत प्रयास किया है।

सतत् विकास का सबसे लोकप्रिय पहलु पर्यावरणीय स्तंभ है। यह वह क्षेत्र है, जहां समाज सबसे समझदार है, और यही वह जगह है, जहां कंपनियों के प्रयासों को निर्देशित किया जाता है। वे सिद्ध करते हैं कि वे पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार हैं और इस प्रकार एक तरफ अपनी प्रतिष्ठा को सरंक्षित करते हैं, और दूसरी तरफ नये ग्राहक प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि निदेशक मंडल अपनी कंपनियों के पर्यावरण प्रदर्शन से अधिक से अधिक रुचि रखते हैं और अधिकारियों को पर्यावरण के अधिक अनुकूल तरीकों से कंपनियों का प्रबंधन करने और इन मुद्दों पर जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सतत् विकास नीति ने ''सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशकों'' की पीडी को जन्म दिया है। वे निवेशक हैं, जो उन कंपनियों के काम को ध्यानपूर्वक समझते हैं, जिनमें वे निवेश करते हैं और उनके सतत् विकास प्रदर्शन पर बहुत रुचि रखते हैं। यह स्पष्ट है कि व्यापारिक नेताओं 'पैसे वाले लोगों' की मानसिकता ने बदलना शुरू कर दिया है और लाभ प्राप्त करना और अधिक पैसा कमाना अब निगम प्रशासन की दुनिया के एकमात्र प्रमुख सिद्धांत नहीं रहा है ,वहां भी सतत् विकास विचारों ने प्रवेश किया है और इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए इसे सुधारने की संभावना है।

14.6 सतत् विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका

शिक्षा और अनुसंधान को स्पष्ट रूप से कई एस डी जी में मान्यता प्राप्त है, इसे संबोधित करने में विश्वविद्यालयों की प्रत्यक्ष भूमिका है। एस डी जी कृषि, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, जेंडर समानता, ऊर्जा उद्योग और नवाचार, मूलभूत ढांचे आदि जैसे क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला का ध्यान रखते हैं और लगभग सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के अंतर्गत शिक्षण, अनुसंधान, सामुदायिक सहभागिता या सलाहकार सेवाओं के माध्यम से योगदान दे सकते हैं। एस डी जी की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नए ज्ञान, चीज़ों को करने के लिए तरीके, प्रतिस्पर्धी विकल्प के बीच कठिन विकल्प और कुछ मामलों में गहन परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

विश्वविद्यालय अनुसंधान, खोज, ज्ञान निर्माण और अभिग्रहण के माध्यम से तकनीकी और सामाजिक प्रगति करते हैं। वे प्रतिभा और रचनात्मकता को आकर्षित और प्रशिक्षित करते हैं और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नवाचार प्रणालियों में केंद्रीय खिलाड़ी है। ये सेवाएं विश्व समुदाय को चुनौतियों, अवसरों और एस डी जी के बीच पारस्परिक क्रियाओं को समझने, समाधान विकसित और कार्यान्वित करने, नीति विकल्पों और परिवर्तन मार्गों का विकास और मूल्यांकन करने और प्रगति की निगरानी करने में महत्त्वपूर्ण हैं।

एस डी जी को प्राप्त करने में विश्वविद्यालयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जो इस प्रकार हैः

- विश्वविद्यालय एस डी जी के कार्यान्वयन को रेखांकित करने के लिए अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और समाधान प्रदान कर सकते हैं, जो कि एस डी जी की चुनौतियों को संबोधित करने के माध्यम से होते हैं, जिन्हें नए ज्ञान और चीज़ों को नये तरीके से करने की आवश्यकता होती है;
- विश्वविद्यालय नीति विकल्पों और कार्यान्वयन मार्गों का विकास और मूल्यांकन कर सकते हैं और प्रगति की निगरानी भी कर सकते हैं;
- विश्वविद्यालय भविष्य के नेताओं, निर्णय–निर्मताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों और नागरिकों को ज्ञान और प्रेरणा के साथ पेशेवर और व्यक्तिगत कौशल और योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं, जो एस डी जी को प्राप्त करने में योगदान दे सकते हैं; और

- विश्वविद्यालय समाज में तटस्थ और विश्वसनीय हितधारकों की पदवी रखते हैं। एस डी जी पर लोक और अन्य क्षेत्रों को शिक्षित करने और एस डी जी के महत्त्व की वकालत करने में भी विश्वविद्यालयों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

सतत् विकास के लिए शिक्षा (Education for Sustainable Development-ESD-ई एस डी) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक अभिन्न तत्व है और सतत् विकास के लिए एक प्रमुख प्रवर्तक के रूप में शिक्षा की अंतरराष्ट्रीय मान्यता बढ़ रही है। सतत् विकास के लिए शिक्षा यानि ई एस डी लोगों को उनके सोचने और सतत भविष्य की दिशा में काम करने के तरीके को बदलने का अधिकार देती है। शिक्षा को पुनर्सृजित करके समाज को बदलना आवश्यक है और यह लोगों को सतत् विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल, मूल्य और व्यवहार विकसित करने में सहायता करती है।

विश्वविद्यालय जटिल और विविध संस्थान हैं। अपने कर्मचारियों, छात्रों, परिसरों, पड़ोस और आपूर्ति शृंखलाओं के माध्यम से, उनके पास महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पद्चिन्ह हैं, जिनके द्वारा अपने स्वयं के शासन, संचालन और संस्कृति के भीतर एस डी जी के सिद्धांतों को लागू करके, विश्वविद्यालय इन व्यापक क्षेत्रों के भीतर एस डी जी की उपलब्धि में प्रत्यक्ष योगदान दे सकते हैं।

विश्वविद्यालय समाज के भीतर तटस्थ और विश्वसनीय हितधारकों की पदवी रखते हैं। इस प्रकार, उनके पास प्रति–क्षेत्रीय संवादों और साझेदारी के माध्यम से एस डी जी को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया देने और मार्गदर्शन करने की क्षमता और जिम्मेदारी है। एस डी जी पर सार्वजनिक या लोक और अन्य क्षेत्रों को शिक्षित करने और एस डी जी के महत्त्व की वकालत करने में भी उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

बोध प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. सतत् विकास में निगमों की क्या भूमिका है?

.....

.....

.....

2. सतत् विकास में विश्वविद्यालयों की भूमिका की चर्चा कीजिए।

.....

.....

.....

14.7 निष्कर्ष

सतत विकास की अवधारणा नागरिकों की भागीदारी और लोकतंत्र की धारणाओं के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है और इसलिए संबंधित हितधारकों के विचारों को प्रकट करना अनिवार्य हो जाता है। एक मज़बूत, अधिक औपचारिक संरचना के माध्यम से व्यवसाय के लिए सतत् विकास प्राप्त करने में विभिन्न गैर–राज्य हितधारकों के योगदानों को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक बेहतर प्रशासन संरचना को इन हितधारकों की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए और भागीदारी के लिए औपचारिक चैनलों या माध्यमों को तैयार करना चाहिए।

14.8 संदर्भ लेख

Bhagwat, P. (2011, March). Corporate Social Responsibility and Sustainable Development. In *Conference on Inclusive & Sustainable Growth*. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Anca-

Turtureanu/publication/227409922_Corporate_Social_Responsibility_and_Sustainable_Development/links/555eeaee08ae86c06b5f5868/Corporate-Social-Responsibility-and-Sustainable-Development.pdf

Gereluk, W. & Royer, L. (2001). *Sustainable Development of the Global Economy: A Trade Union Perspective*. Geneva: ILO.

Kilgy, P. (2011). *NGOs in India: The Challenge of Women's Empowerment and Accountability*. Routledge.

Kolk, A. (2016). The Social Responsibility of International Business: From Ethics and the Environment to CSR and Sustainable Development. *Journal of World Business*. 51(1), 23-34.

Kolk, A., & Van Tulder, R. (2010). International Business, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development. *International business review*. 19(2), 119-125.

Nanda, N. (2000). The Emerging Role of NGOs in Rural Development in India. *Social Change.* 30(3&4), 36-43.

Pacheo-Vega, R. (2010). NGOs and Sustainable Development. Retrieved from file:///C:/Users/Admin/Downloads/Pacheco-Vega2010NGO SandsustainabledevelopmentNInternationalEncyclopaedia.27-32.pdf.

Sandhu, D., & Arora, P. (2012). Role and Impact of Environmental NGO's on Environmental Sustainability in India. *Gian Jyotie Journal*. 1(3).

Sen, S. (1999). Some Aspects of State–NGO Relationships in India in the Post-independence Era. *Development and Change*. 30(2), 327-355

Van Tulder, R., & Keen, N. 2018. Capturing Collaborative Challenges: Designing Complexity-Sensitive Theories of Change for Cross-Sector Partnerships. *Journal of Business Ethics*. 94(1), 85-101.

Van Zanten, J. A., & Van Tulder, R. (2018). Multinational Enterprises and the Sustainable Development Goals: An Institutional Approach to Corporate Engagement. *Journal of International Business Policy*. 1(3-4), 208-233.

Wagner, L. M. (1999). Negotiations in the UN Commission on Sustainable Development: Coalitions, Processes and Outcomes. *International Negotiation*. 4(2), 107-131

14.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः

- सतत् विकास अनिवार्य मानव आवश्यकताएं प्रदान करता है।
- यह कृषि आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है।
- जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक है।
- वित्तीय सततता लाने के लिए यह अनिवार्य है।
- जैव–विविधता को बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता है।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**

- गैर–सरकारी संगठन एस डी जी को लागू करने में राज्य पर प्रभाव डाल सकते हैं।
- यह संसाधन विकास पहलों के सामाजिक प्रभाव की निगरानी करते हैं।
- इनमें से कुछ पर्यावरणीय प्रभाव की निगरानी करते हैं।
- वे अभिनव तरीके विकसित करते हैं, और नीति में अनुरूप परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं।
- वे वकालत और पैरवी द्वारा, बढ़ते नेटवर्क और सीमांत समूहों को लक्षित करके सतत् विकास प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

बोध प्रश्न 2

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**

- सी एस आर तीन स्तंभो, आर्थिक, पारिस्थितिक और सामाजिक, मुद्दों पर आधारित है;
- आंतरिक नियंत्रण सुधार को अपनाना;
- कर्मचारियों को काम पर रखने और भेदभाव को रोकने में विविधता के लिए प्रतिबद्धता;
- प्रबंधन दल, जो कर्मचारियों को लागत की अपेक्षा संपत्ति के रूप में देखते हैं;
- उच्च प्रदर्शन कार्यस्थल जहां निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कार्यक्षेत्र कर्मचारियों के विचारों को एकीकृत किया जाता है।
- संचालन नीतियों का अपनाना, जो सामाजिक और पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन से अधिक है, उन्नत संसाधन उत्पादकता, अधिक उत्पादक, कुशल और लाभदायक फैशन जैसे पुनर्नवीनीकरण सामग्री और उत्पाद की पुनरावृत्ति करने में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर केंद्रित है।
- उन स्थितियों के लिए जिम्मेदारी लेना, जिनके अंतर्गत सामान का उत्पादन प्रत्यक्ष या अनुबंध कर्मचारियों द्वारा देश या विदेश में किया जाता है।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**

- विश्वविद्यालय एस डी जी के कार्यान्वयन को रेखांकित करने के लिए ज्ञान, नई पद्धतियाँ/नवाचार और समाधान प्रदान कर सकते हैं।
- विश्वविद्यालय नीति विकल्पों और कार्यान्वयन मार्गों का विकास और मूल्यांकन कर सकता है और प्रगति की निगरानी भी कर सकता है।
- विश्वविद्यालय भविष्य के नेताओं, निर्णय–निर्माताओं, नवप्रवर्तकों, उद्यमियों और नागरिकों को ज्ञान और प्रेरणा देने के साथ पेशेवर और व्यक्तिगत कौशल और क्षमताएं प्रदान कर सकते हैं, जो एस डी जी को प्राप्त करने में योगदान कर सकते हैं।
- विश्वविद्यालय समाज में तटस्थ और विश्वसनीय हितधारकों की पदवी रखते हैं। एस डी जी की लोक और अन्य क्षेत्रों को शिक्षित करने और एस डी जी के महत्त्व की वकालत करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।